



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 4 अप्रैल, 2005 / 14 चैत्र, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-171 004, 4 अप्रैल, 2005

संख्या वि० स० विधायन-गवर्नमेंट बिल/1-26/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक-11)

जो आज दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

जे० आर० गाजटा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

2005 का विधेयक संख्यांक 11

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में, कृषि उपज के विपणन, दक्षतापूर्ण विपणन प्रणाली के विकास, कृषि सम्बन्धी प्रसंस्करण और कृषि निर्यात, स्थापन के उन्नयन और कृषि उपज के लिए मण्डियों के उचित प्रशासन हेतु समुन्नत विनियमन का उपबन्ध करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में और से कृषि उपज के विपणन के लिए सुप्रशासित और दक्षतापूर्ण अवसंरचना की अभिवृद्धि करने हेतु, प्रसुविधाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए न्यूनतम मानकों के व्यवस्थापन के माध्यम से परिचालन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों के लिए सन्तुलित व्यापार क्षेत्र (लैवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने हेतु विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि एवं संक्षिप्त नाम। औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 है।

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई परिभाषाएँ। बात विरुद्ध न हो,—

(क) “कृषि उपज” से इस अधिनियम की अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट या इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा घोषित कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, पशुधन और पशुधन

उत्पाद, ऊन (कच्ची ऊन) और पशुओं की खाल, वन उत्पाद और मछली उद्योग के समस्त उत्पाद और वस्तुएं, चाहे प्रसंस्कृत हो या अप्रसंस्कृत हो, अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत ऐसे दो उत्पादों का मिश्रण या दो से अधिक का मिश्रण भी सम्मिलित है;

- (ख) "कृषक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी है और जिसकी हिमाचल प्रदेश में अपनी भूमि हो और जो या तो स्वयं या भाड़े के श्रमिकों द्वारा या अन्यथा कृषि उपज के उत्पादन के काम में लगा हुआ है परन्तु इसके अन्तर्गत कोई मण्डी कृत्यकारी नहीं है;
- (ग) "बोर्ड" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (घ) "कारबार" से कृषि उपज का विक्रय, प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन, मण्डारकरण, परिवहन और सम्बन्धित क्रियाकलाप अभिप्रेत है;
- (ङ) "क्रेता" से कोई फर्म, कम्पनी या सहकारी सोसाइटी या सरकारी अभिकरण, लोक उपक्रम/लोक अभिकरण या निगम, कमीशन अभिकर्ता अभिप्रेत है, जो या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति या अभिकर्ता की ओर से अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है;
- (च) "उप-विधियों" से इस अधिनियम की धारा 84 के अधीन बोर्ड द्वारा समिति के लिए बनाई गई उप-विधियां अभिप्रेत हैं;
- (छ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ज) "कमीशन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने

मुख्य व्यापारी की ओर से और ऐसे संव्यवहार पर अन्तर्वलित रकम पर प्रतिफल स्वरूप कमीशन या प्रतिशतता पर कृषि उपज का क्रय करता है और संदाय करता है, इसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में इसे मुख्य व्यापारी को परिदत्त करता है या जो मण्डी क्षेत्र के भीतर या मण्डी क्षेत्र से बाहर से, बिक्री के लिए भेजी गई कृषि उपज को प्राप्त करता है और अपनी अभिरक्षा में लेता है, उसका मण्डी क्षेत्र में विक्रय करता है और क्रेता से उसके संदाय का संग्रहण करता है और विक्रय आगमों को अपने मुख्य व्यापारी को प्रेषित करता है;

(झ) "समिति" से धारा 29 के अधीन स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(ज) "संविदा खेती" से "संविदा खेती उत्पादक" के नाम से ज्ञात व्यक्ति द्वारा संविदा खेती प्रायोजक के नाम से ज्ञात दूसरे व्यक्ति के साथ इस प्रभाव के लिखित करार, कि उसके फार्म की उपज का करार में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार व्यय किया जाएगा, के अधीन खेती अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.— "संविदा खेती उत्पादक" से तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भी नाम से ज्ञात कोई वैयक्तिक कृषक या कृषकों का संगम अभिप्रेत है;

(ट) "संविदा खेती करार" से संविदा खेती प्रायोजक और संविदा खेती उत्पादक के मध्य संविदा खेती के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किया गया करार अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.— "संविदा खेती प्रायोजक" से कोई एकमात्र स्वत्वधारी, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कम्पनी, भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भागीदारी फर्म, कोई सरकारी अभिकरण, हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियां अभिप्रेत है और इसके

अन्तर्गत इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि और समनुदेशिनी भी हैं;

- (उ) "सहकारी सोसाइटी" से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्पादकों की सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो कृषि उपज के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण, या मण्डारकरण में व्यवहार करती है, या अन्यथा कृषि उपज के निपटाए जाने के कारबार में लगी हुई है;
- (ड) "निर्यात" से कृषि उपज को भारत से बाहर भेजना अभिप्रेत है;
- (ढ) "निर्यातक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि उपज का निर्यात करता है;
- (ण) "ई-ट्रेडिंग" से ऐसा व्यापार (ट्रेडिंग) अभिप्रेत है जिसमें बिल बनाना, बुकिंग करना, संविदाकारी, वार्ता करना, सूचना का आदान प्रदान, अभिलेख रखना तथा अन्य सम्बन्धित क्रियाकलाप कम्प्यूटर/नेटवर्क पर इलेक्ट्रोनिकली किए जाते हैं;
- (त) "हैमल" से ढारा बनाने, लदान करने, माल उतारने, मराई करने, सिलाई करने, खाली करने या किसी कृषि उपज को अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में ले जाने के कार्य के लिए लगा हुआ कोई मजदूर, हैमल या कुली, अभिप्रेत है;
- (थ) "आयात" से कृषि उपज को भारत के बाहर से लाना अभिप्रेत है;
- (द) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद को भारत के बाहर से आयात करता है;
- (ध) "अनुज्ञप्ति" से इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

- (न) "अनुज्ञप्तिधारी" से इस अधिनियम के अधीन जारी अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई व्यक्ति या कोई संगम, फर्म, कम्पनी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या सोसाइटी अभिप्रेत है;
- (प) "मण्डी" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्थापित मण्डी अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र, मण्डी प्रांगण/उप-प्रांगण और मुख्य मण्डी प्रांगण अभिप्रेत है;
- (फ) "मण्डी क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र अभिप्रेत है;
- (ब) "मण्डी प्रभार" के अन्तर्गत कमीशन, दलाली, वजन करना, माप करना, हैमेलिंग (लदान करने, माल उतारने या वहन करने) सफाई करना, सुखाना, छानना, सिलाई, चट्टा लगाना, भाड़े पर लेना, टाट बोरियां (गन्नी बैग्स), मुद्रांकन, बैगिंग मण्डारकरण, मांडागारण, श्रेणीकरण, सर्वेक्षण, वहन और प्रसंस्करण के मद्दे या के बाबत प्रभार है;
- (म) "मण्डी कृत्यकारी" से कोई व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, क्रेता, हैमल, संसाधक, स्टाकिस्ट और कोई अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मण्डी कृत्यकारी घोषित किया जाए, अभिप्रेत है;
- (म) मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में "मण्डी प्रांगण" से कोई विनिर्दिष्ट स्थान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस रूप में घोषित किसी मण्डी क्षेत्र में कोई अहातें, भवन या परिक्षेत्र है;
- (य) "सदस्य" के अन्तर्गत बोर्ड का अध्यक्ष भी है;
- (यक) "विपणन" से फसल कटाई की अवस्था से प्रारम्भ होकर, अन्त में इसके उपभोक्ताओं तक पहुंचने तक, उत्पादन स्थलों से कृषि उपज के प्रचुर मात्रा में पहुंचने तक अन्तर्वलित समस्त क्रियाकलाप अर्थात्, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, मण्डारकरण, परिवहन, वितरण प्रणाली और अन्य समस्त कार्य जो प्रसंस्करण में अन्तर्वलित हैं, अभिप्रेत है;

(यख) "अधिसूचना" से इन अधिनियम के अधीन जारी और राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(यग) "अधिसूचित कृषि उपज" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन अधिसूचित कोई कृषि उपज अभिप्रेत है;

(यघ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या कोई संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, है;

(यङ) "उत्पादक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने उप-व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में, यथास्थिति, स्वयं, अभिधारियों के माध्यम से या अन्यथा कृषि उपज उगाता है, उत्पादन करता है, पालता या पैदा करता है, परन्तु इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति नहीं है जो व्याहारी या दलाल के रूप में कार्य करता है या जो व्याहारियों या दलालों की फर्म का भागीदार है या अन्यथा, उसके द्वारा या अभिधारियों के माध्यम से उगाई गई, उत्पादित, पाली गई या पैदा की गई कृषि उपज से भिन्न, कृषि उपज के निपटाए जाने या मण्डारकरण के कारबार में लगा हुआ है:

परन्तु कोई व्यक्ति उत्पादक होने से केवल इस आधार पर निरहिंत नहीं किया जाएगा कि वह सहकारी सोसाइटी का सदस्य है;

स्पष्टीकरण.— "उत्पादक" पद के अन्तर्गत अभिधारी भी सम्मिलित है।

(यच) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(यछ) "प्रसंस्करण" से अधिकचरी कृषि उपज या इसके उत्पाद के एक या अधिक उपचारों की शृंखला, जो पाउडर बनाने, पीसने, छीलने, मूसी निकालने, उसनने, पालिश करने, ओटाई, पेरने (दबाने), तराई, सफाई या कोई अन्य

शारीरिक, यान्त्रिक, रसायनिक या भौतिक उपचार से सम्बन्धित है, अभिप्रेत है;

- (यज) "संसाधक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या प्रभार के संदाय पर किसी अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण का जिम्मा लेता है;
- (यझ) "निजी मण्डी प्रांगण" से मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगण/ उप-मण्डी प्रांगण से भिन्न ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जहां इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति रखने वाले, किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए अवसंरचना का विकास और व्यवस्था की हो;
- (यड) "रजिस्ट्रीकरण" से इस अधिनियम के अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है;
- (यट) "विनियम" से इस अधिनियम की धारा 85 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;
- (यठ) "परचून बिक्री" से ऐसी मात्रा से अनधिक कृषि उपज बिक्री अभिप्रेत है, जो विहित की जाए;
- (यड) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (यद) "विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कृषि उपज का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है;
- (यण) "व्यापारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या विक्रय करता है और इसमें कृषि उपज के प्रसंस्करण में लगा हुआ व्यक्ति भी है परन्तु कोई कृषक

इसमें सम्मिलित नहीं है;

(यत) "परिवहन" से कारबार के अनक्रम में विपणन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ठेला, बैलगाड़ी, ट्रक या किसी अन्य यान पर कृषि उपज ले जाना अभिप्रेत है;

(यथ) "परिवाहक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि उपज का परिवहन करता है; और

(यद) "मूल्य परिवर्धन" से प्रसंस्करण, श्रेणीकरण, पैकिंग या अन्य क्रियाकलाप अभिप्रेत है, जिनके कारण कृषि उपज के मूल्य में परिवर्धन होता है।

अध्याय-2

बोर्ड की स्थापना, गठन, शक्तियाँ और कृत्य

बोर्ड की
स्थापना।

3. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, मण्डियों के क्रियाकलापों के समन्वय के लिए और कृषि विपणन के विकास, उन्नयन (संवर्धन) और विनियमन के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना करेगी।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और यह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने तथा ऐसी किसी सम्पत्ति को पट्टे पर देने, विक्रय करने या संविदा में अन्यथा अन्तरित करने और ऐसे सभी कार्य करने जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है; के लिए सक्षम होगा।

बोर्ड का
गठन।

4. बोर्ड का एक अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और उपाध्यक्ष सहित बीस सदस्य होंगे जिनमें से दस पदेन सदस्य और दस गैर-सरकारी सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) पदेन सदस्य :—

(i) सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार—उपाध्यक्ष;

- (ii) सचिव (औद्यानिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iii) सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (iv) सचिव (वन) हिमाचल प्रदेश सरकार;
- (v) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश;
- (vi) निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश;
- (vii) निदेशक, औद्यानिकी, हिमाचल प्रदेश;
- (viii) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश;
- (ix) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, बैंक शिमला का मुख्य महाप्रबन्धक, और
- (x) हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक।

(ख) गैर सरकारी सदस्य,—

- (i) समितियों के दो अध्यक्ष होंगे;
- (ii) चार, अन्य प्रगतिशील कृषक/किसान होंगे;
- (iii) दो ऐसे व्यापारियों में से होंगे, जो इस अधिनियम की धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं; और
- (iv) दो कृषि विपणन में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों में से होंगे।

5. (1) बोर्ड का अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। समिति के अधिक्रमण की दशा में, जहां से सदस्यों को बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किया गया है, सम्बन्धित सदस्य बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष और पदेन सदस्यों की पदावधि समाप्त हो जाएगी जैसे ही वह उस पद को छोड़ देता है जिसके फलस्वरूप वह नामनिर्दिष्ट किया गया था।

(3) जब जब अध्यक्ष के पद में अस्थाई रिक्ति होती है, तो ऐसी रिक्ति के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

6. कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, जो —

बोर्ड के सदस्यों की निरर्हता।

- (क) साधारणतया हिमाचल प्रदेश में निवास नहीं करता है;
- (ख) पच्चीस वर्ष से कम आयु का है;
- (ग) इस अधिनियम की धारा 8 या धारा 33 के अधीन हटाया गया है;
- (घ) विकृत चित है; और
- (ङ) दिवालिया घोषित किया गया है या चाहे हिमाचल प्रदेश में या इसके बाहर, नैतिक अद्यमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है:

परन्तु यह कि खण्ड (ङ) के अधीन, दण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर निरर्हता, उस तारीख, जिस को कि उस व्यक्ति की सजा की समाप्ति हुई थी, से चार वर्ष के अवसान के पश्चात् लागू नहीं होगी।

बोर्ड के सदस्यों का त्यागपत्र।

7. बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र निविदत्त कर पद त्याग कर सकेगा, और बोर्ड के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से, राज्य सरकार को अपना त्यागपत्र निविदत्त कर सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा, और, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य का स्थान, उसके त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने की तारीख से रिक्त हो जाएगा।

बोर्ड के सदस्यों का हटाया जाना।

8. राज्य सरकार, बोर्ड के किसी भी गैर सरकारी सदस्य को हटा सकेगी जो धारा 6 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन हो जाता है, या जो उसकी राय में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असावधानी बरतता है या जिसका बोर्ड के सदस्य के रूप में रहना इसके हित में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और उस प्रवर्ग में से जिससे हटाया गया सदस्य सम्बन्ध रखता हो, उसके स्थान पर किसी अन्य सदस्य को धारा 4 के अधीन उपबंधित रीति में, नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु किसी सदस्य को हटाने से पूर्व प्रस्तावित कार्रवाई के कारण उसे संसूचित किए जाएंगे और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उससे जवाब

मांगा जाएगा और सम्यक् रूप से उस पर विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी गैर सरकारी सदस्य की रिक्ति यथासाध्यशीघ्र भरी जाएगी।

9. (1) बोर्ड का एक प्रबन्ध निदेशक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा।

बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबन्ध निदेशक बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

(3) बोर्ड और समितियों के कर्तव्यों और कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए, बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सिविल इंजीनियर और कर्मचारियों सहित, ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा जैसे आवश्यक हो।

(4) बोर्ड और समितियों के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

10. बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को विपणन विकास निधि से ऐसी बैठक फीस और भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जैसे विहित किए जाएं।

बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते।

11. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा और उसे ऐसे कार्य करने की शक्ति होगी जो इन कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए अनिवार्य या समीचीन है :—

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

(i) इस अधिनियम के अधीन स्थापित और गठित समस्त समितियों पर अधीक्षण और नियन्त्रण रखना;

(ii) मण्डियों और मण्डी क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसी समितियों द्वारा जिम्मा लिए गए कार्यक्रमों सहित समितियों की कार्यप्रणाली और उसके अन्य कार्यकलापों का समन्वय

करना;

(iii) कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिए राज्य स्तरीय योजना का जिम्मा लेना;

(iv) विपणन विकास निधि का प्रशासन चलाना;

(v) समितियों को साधारणतया या किसी समिति को विशिष्टतः उसकी अभिवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निदेश देना;

(vi) इस अधिनियम द्वारा इसे विनिर्दिष्टतः न्यस्त कोई अन्य कृत्य; और

(vii) इसी प्रकृति के कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को, न्यस्त किए जा सकेंगे।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के ऐसे कृत्यों के अन्तर्गत—

(i) मुख्य या उप-मण्डी प्रांगण की स्थापना के लिए समितियों द्वारा नए स्थलों के चयन के प्रस्तावों को अनुमोदित करना;

(ii) मण्डी क्षेत्र में अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करने, जैसे श्रेणीकरण, पैक हाऊसिज, मण्डारकरण, प्रसंस्करण, फसल कटाई के पश्चात् की अन्य प्राबन्धिक सुविधाओं इत्यादि के लिए प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(iii) समिति द्वारा जिम्मा लिए गए विनिर्माण प्रोग्रामों की योजनाओं और प्राक्कलनों की तैयारी में समिति का पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना;

(iv) बोर्ड की निधि द्वारा प्रभार्य समस्त कार्यों का निष्पादन करना;

- (v) लेखे रखना और उन्हें ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में लेखा परीक्षा करवाना जैसी विहित की जाए;
- (vi) वर्ष की समाप्ति पर प्रतिवर्ष अपनी प्रगति रिपोर्ट, तुलनपत्र और परिसंपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रकाशित करना और बोर्ड के प्रत्येक सदस्य और राज्य सरकार को इसकी प्रतियां भेजना;
- (vii) विपणन प्रौद्योगिकी और विस्तार सेवाओं के अन्तरण के लिए बोर्ड में विपणन विस्तार क्रियाकलापों की जिम्मेवारी लेना। यह किसी कृषि उपज के विनियमित विपणन और विपणन के विकास से सम्बन्धित मामलों पर सम्प्रचार (प्रोपेगैन्डा) और प्रचार के लिए आवश्यक प्रबन्ध भी करेगा;
- (viii) सभी स्तरों पर कृषि विपणन में प्रशिक्षित व्यक्ति विशेष की मांग का निर्धारण करने के पश्चात् समितियों और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का उपबन्ध करना;
- (ix) आगामी वर्ष के लिए बजट तैयार करना और अंगीकृत करना;
- (x) कृषि विपणन से सम्बन्धित विषयों पर सेमीनारों/कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों इत्यादि का प्रबन्ध और आयोजन करना;
- (xi) ऐसे अन्य कार्य करना जो समितियों के सामान्य हित में हो या बोर्ड के दक्षतापूर्ण कृत्यों के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
- (xii) अधिसूचित कृषि उपज और ई-ट्रेडिंग के श्रेणीकरण और मानकीकरण का संचालन और उन्नयन करना; और

- (xiii) राज्य में कृषि उपज के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुण प्रमाणीकरण के उन्नयन के प्रयोजन के लिए यथाविहित कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो का गठन करना।

बोर्ड के
प्रबन्ध
निदेशक की
शक्तियाँ
और कृत्य।

12. बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक,—

- (i) लेखों और अभिलेखों से सम्बन्धित कार्यपालक प्रशासन के विषय में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना और प्रक्रिया, जो विहित की जा सकेगी, के अनुसार कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित समस्त प्रश्नों का निपटारा करेगा;
- (ii) कार्य की स्वीकृत मदों पर विपणन विकास निधि से व्यय उपगत करेगा;
- (iii) उसके पास वैसी ही शक्तियाँ होंगी जैसी राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रदत्त की गई हैं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे विहित किए जाएं,
- (iv) प्रशासनिक आधारों पर एक समिति के कर्मचारियों को बोर्ड में और विपर्ययेन स्थानान्तरित करने की शक्ति होगी;
- (v) आपातकाल की दशा में किसी कार्य का निष्पादन या बन्द करना या ऐसा कार्य करना जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित है, निर्दिष्ट करेगा;
- (vi) बोर्ड का वार्षिक बजट तैयार करेगा;
- (vii) बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा के लिए व्यवस्था करेगा;
- (viii) बोर्ड की बैठकों की व्यवस्था करेगा और यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों का

अभिलेख रखेगा;

- (ix) ऐसे कदम उठाएगा जो बोर्ड के विनिश्चयों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे जाएं;
- (x) समितियों द्वारा चाहे उनकी अपनी निधियों से, या ऋण से और या बोर्ड द्वारा या किसी अन्य अभिकरण से उपलब्ध करवाए गए अनुदान से जिम्मा लिए गए निर्माण कार्य का निरीक्षण करेगा और सुधार के उपाय करेगा;
- (xi) समितियों या बोर्ड के ऐसे कृत्यों, जहाँ इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के अधीन बनाए गए उपबन्धों के प्रतिकूल हैं, की राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा; और
- (xii) ऐसे कदम उठाएगा जो बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

13. (1) बोर्ड अपने कारबार के संव्यवहार के लिए प्रत्येक बोर्ड की तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे स्थान और ऐसे समय पर बैठक बैठक। करेगा जैसा अध्यक्ष अवधारित करें।

(2) बोर्ड की समस्त कार्यवाहियां, बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित की जाएगी।

(3) बोर्ड ऐसी रीति में कारबार का संचालन करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए।

14. बोर्ड की बैठक में कुल सदस्यों के एक तिहाई से गणपूर्ति। गणपूर्ति होगी। समस्त प्रश्न जो बोर्ड के बैठक में उठ सकते हैं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किए जाएंगे और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा :

परन्तु यह कि यदि कोई बैठक गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दिया जाता है, तो उसी कारबार के संव्यवहार के लिये बुलाई गई अगली बैठक में गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

बोर्ड के
कार्य का
अविधिमान्य
न होना।

15. बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाहियाँ, केवल इसके सदस्यों में से किसी रिक्ति होने के या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

उप-समितियों
की नियुक्ति।

16. बोर्ड, इसके किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का अनुपालन करने के लिये या उससे अनुषांगिक किसी विषय पर परामर्श देने के लिये, तीन या उससे अधिक सदस्यों से गठित, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक भी सम्मिलित होगा, उप समितियाँ नियुक्त कर सकेगा और इसके किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों को, जिसे यह आवश्यक समझे, ऐसी उप-समिति को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

बोर्ड का
अधीक्षण
और
नियन्त्रण।

17. राज्य सरकार, बोर्ड और इसके अधिकारियों पर अधीक्षण और नियन्त्रण रखेगी और ऐसी जानकारी, जैसी यह आवश्यक समझे, मंगवा सकेगी और इसका यह समाधान हो जाने की दशा में, कि बोर्ड उचित रूप में कार्य नहीं कर रहा है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या भ्रष्टाचार या कुप्रबन्ध का दोषी है, तो यह बोर्ड को निलंबित कर सकेगी, और उस समय तक, जब तक कि नए बोर्ड का गठन नहीं हो जाता, बोर्ड के कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी यह उचित समझे :

परन्तु यह कि बोर्ड, के निलंबन की तारीख से छह मास के भीतर इसका गठन किया जायेगा।

शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

18. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उसको प्रदत्त किन्हीं शक्तियों, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय, को बोर्ड को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, बोर्ड साधारण या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक को या इसके द्वारा नियुक्त उप-समिति को या बोर्ड के किसी अधिकारी को, इस अधिनियम के द्वारा

या के अधीन इसे प्रदत्त किन्हीं शक्तियों और कर्तव्यों को, जैसा यह उचित समझें, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय-3

व्यापार विनियमन और संविदा खेती

19. (1) राज्य सरकार या तो स्वयं या उत्पादकों (गोअरज) द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर या बोर्ड की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर जन साधारण से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करके, जिन पर इसके द्वारा विचार किया जाएगा, ऐसी कृषि उपज के क्रय, मंडारकरण, प्रसंस्करण और विक्रय पर नियन्त्रण रखने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

अधिसूचित
कृषि उपज
के विपणन
को विकसित
करने और
विनियमित
करने के
आशय की
अधिसूचना।

(2) उप धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात्, और विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी आवश्यक हो, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को या उसके किसी भाग को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मण्डी क्षेत्र घोषित कर सकेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के समस्त या किसी भी प्रकार के विपणन को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे मण्डी क्षेत्र में विकसित और विनियमित किया जाता।

20. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में, उसके आसपास के किसी अन्य क्षेत्र को उसमें सम्मिलित करते हुए या उसमें समाविष्ट किसी क्षेत्र को उससे अपवर्जित करते हुए, परिवर्तन करने; या

(ख) दो या दो से अधिक मण्डी क्षेत्रों का सामेलन करने और उनकी एक समिति गठित करने, या

मण्डी को
अस्थापित
करने के
लिए मण्डी
क्षेत्रों की
सीमाओं में
परिवर्तन
करने या
विभाजन
करने के
आशय की
अधिसूचना।

(ग) मण्डी क्षेत्र को विभाजित करने और उससे दो या दो से अधिक समितियां गठित करने, या

(घ) मण्डी को अस्थापित करने, की अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, यथास्थिति, मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र, या मण्डी क्षेत्र जिसका एक में सम्मेलन किया जाना है या प्रत्येक मण्डी के क्षेत्र को अस्थापित किया जाना है, की सीमाएं परिभाषित करेगी और ऐसी अवधि, को भी विनिर्दिष्ट करेगी जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, प्राप्त किए जा सकेंगे, से छह सप्ताह से कम नहीं होगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना से संभाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य सरकार को लिखित में अपने आक्षेपों या सुझावों को प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन नियत अवधि के भीतर प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर, राज्य सरकार द्वारा विचार और विनिश्चय किया जायेगा और तत्पश्चात् राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा,—

(क) क्षेत्र या उसके किसी भाग को मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित या उसे उससे अपवर्जित कर सकेगी;

(ख) सम्मेलित किए गए मण्डी क्षेत्र के लिये नई समिति का गठन कर सकेगी; या

(ग) विद्यमान मण्डी क्षेत्र को विभाजित कर सकेगी और यथास्थिति, ऐसे क्षेत्रों के लिए दो या दो से अधिक समितियों का गठन कर सकेगी; या

(घ) मण्डी को अस्थापित कर सकेगी।

(5) जहाँ उप-धारा (4) के अधीन किसी क्षेत्र को मण्डी क्षेत्र से अपवर्जित करते हुए और ऐसे क्षेत्र को अन्य मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए, अधिसूचना जारी की गई है, तो राज्य सरकार बोर्ड और सम्बन्धित समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह निर्धारित करने के लिए कि एक समिति में निहित परिसम्पत्तियों और अन्य सम्पत्तियों का कौन सा भाग दूसरी समिति में निहित होगा और किस रीति में समितियों की देनदारियों को, दो समितियों के बीच प्रभाजित किया जायेगा, स्कीम विरचित करेगी, और ऐसी स्कीम राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

21. (1) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित हो सकेंगे,—
- (i) समिति द्वारा संचालित मण्डी प्रांगण;
- (ii) समिति द्वारा संचालित एक या एक से अधिक उपमण्डी प्रांगण; और
- (iii) समिति से भिन्न व्यक्ति द्वारा संचालित प्राइवेट मण्डी प्रांगण, प्राइवेट मण्डियाँ, किसानों और उपमोक्ताओं की मण्डियाँ।

मण्डी प्रांगण
उप-मण्डी
प्रांगण,
किसान,
उपमोक्ता
और प्राइवेट
मण्डी
प्रांगण।

(2) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, मण्डी क्षेत्र में किसी संरचना, अहाते, खुले स्थान या परिक्षेत्र सहित किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिये, मण्डी प्रांगण या उप-मण्डी प्रांगण, घोषित कर सकेगा।

22. कोई व्यक्ति, जो कृषक से सीधे कृषि उपज क्रय करने के लिए प्राइवेट प्रांगण स्थापित करने या किसी मण्डी क्षेत्र में,—
- (क) अधिसूचित कृषि उपज का प्रसंस्करण;
- (ख) विशिष्ट विनिर्देश की अधिसूचित कृषि उपज का व्यापार;
- (ग) अधिसूचित कृषि उपज का निर्यात; और
- (घ) अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन द्वारा अन्य प्रकार से श्रेणीकरण, पैकिंग और संव्यवहार,

प्राइवेट
प्रांगणों की
स्थापना
और कृषकों
से कृषि
उपज का
सीधा क्रय।

करने हेतु अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध करने की वांछा रखता है, तो वह इस अधिनियम की धारा 25 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन करेगा।

उपभोक्ता
और किसान
मण्डियों की
स्थापना
और
किस्मती/कृषकों
द्वारा
पशु-सलवन
प्रबन्धन
प्रसुविधाओं
का सृजन।

23. (1) किसी मण्डी क्षेत्र में, किसी व्यक्ति द्वारा अवसंरचना जो विहित की जाए, विकसित करते हुए उपभोक्ता या किसान मण्डी स्थापित की जा सकेगी और उत्पादक, स्वयं अपनी कृषि उपज, ऐसे मण्डी क्षेत्र में उपभोक्ता को, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, सीधे बेच सकेगा।

(2) कृषि उपज के विक्रय पर मण्डी सेवा प्रभार विक्रेता द्वारा, संगृहीत किया जाएगा और उपभोक्ता मण्डी के स्वत्वधारी को प्रेषित किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपभोक्ता या किसान मण्डी में किए गए संव्यवहारों पर कोई मण्डी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी किसान और कृषक, अपने वास्तविक उपयोग के लिए फार्म स्तर पर पशु-सलवन प्रबन्धन (पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट) अवसंरचना प्रसुविधाओं, जैसे कि श्रेणीकरण, मानकीकरण, पैक हाऊजिंग, मण्डारकरण (जिसमें शीतागार भी सम्मिलित हैं), कृषि उत्पाद का प्रारम्भिक प्रसंस्करण और अन्य पशु-सलवन प्रबन्धन (पोस्ट हारवेस्ट मैनेजमेंट) प्रसुविधाओं का सृजन कर सकेगी जिनके लिए केन्द्रीय या राज्य सरकार, मिन्न स्कीम उपबन्धित कर सकेगी जिसे विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय भारत सरकार के माध्यम से उद्यान विभाग द्वारा निष्पादित किए जा रहे उद्यान प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन स्कीम सहित कार्यान्वित किया जा सकेगा।

संविदा
खेती।

24. कोई भी व्यक्ति, जब तक इस अधिनियम की धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हो जाता, संविदा नहीं करेगा, और उसे संविदा खेती उत्पादक के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, करार करना होगा।

25. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 22 के अधीन अधिसूचित कृषि उपज, का कृषकों या उत्पादक से सीधे क्रय करने की वांछा रखता है या प्राइवेट मण्डी प्रांगण स्थापित करने की इच्छा रखता है या धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन एक या एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में उपभोक्ता या किसान मण्डी स्थापित करने की वांछा रखता है, तो वह बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक को, ऐसी अवधि के लिये, ऐसे प्ररूप में, ऐसी शर्तों और, ऐसी फीसों के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति को प्रदान करने या नवीकृत करने के लिए आवेदन करेगा।

प्राइवेट प्रांगण, उपभोक्ता और किसान मण्डी को अनुज्ञप्ति प्रदान करना तथा उसका नवीकरण।

(2) अनुज्ञप्ति प्रदान करने और नवीकरण के लिये उप-धारा (1) के अधीन, प्राप्त किए गए आवेदन को स्वीकृत या कारण को लिखित में अभिलिखित करते हुए अस्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु अनुज्ञप्ति को प्रदान या नवीकृत नहीं किया जाएगा यदि,—

- (i) आवेदक के विरुद्ध समिति देय बकाया है;
- (ii) आवेदक अवयस्क हैं या वास्तविक नहीं हैं;
- (iii) आवेदक, अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और उप-विधियों के अधीन व्यतिक्रमी घोषित है;
- (iv) आवेदक, किसी आपराधिक मामले में दोषी घोषित किया गया हो और कारावास से दण्डित हो;
- (v) राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना या नवीकृत किया जाना उत्पादकों के हितों का उन्नयन (अभिवृद्धि) करने वाला नहीं है;
- (vi) कोई अन्य कारण, जिसे बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक, उत्पादक या उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध समझता है।

26. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, धारा 25 के अधीन जारी की गई या नवीकृत की गई कोई अनुज्ञप्ति, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा, ऐसे अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :—

अनुज्ञप्ति रद्द और निलंबित करने की शक्ति।

- (क) यदि अनुज्ञप्ति, जानबूझ कर दुर्यपदेशन या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है; या

- (ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या उसका कोई सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के किन्हीं निबंधनों या शर्तों को भंग करता है; या
- (ग) यदि कोई अनुज्ञप्ति धारक अन्य अनुज्ञप्ति धारक के साथ मिल कर कोई कार्य करता है या मण्डी प्रांगण/उप मण्डी प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन में जानबूझ कर बाधा पहुंचाने, स्थगित करने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में अपने सामान्य कारबार को चलाने में परिवर्जन करता है तथा जिसके परिणामस्वरूप किसी अधिसूचित कृषि उपज का विपणन बाधित होता है, स्थगित होता है या रुक जाता है;
- (घ) यदि अनुज्ञप्ति धारक दिवालिया हो जाता है; या
- (ङ.) यदि अनुज्ञप्ति धारक, कोई निरर्हता, जो विहित की जाए, से ग्रस्त हो जाता है; या
- (च) यदि अनुज्ञप्ति धारक, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है, यदि दोषसिद्धि प्रथम बार है तो एक वर्ष के भीतर और पश्चात्तर्वर्ती दोषसिद्धि के लिये तीन वर्ष के भीतर।

अधिसूचित
कृषि उपज
के विपणन
का
विनियमन।

27. (1) कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम या नियमों और तदधीन बनाई गई उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार के सिवाय,—

- (i) मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज के विपणन के लिए किसी स्थान का उपयोग नहीं करेगा; और
- (ii) मण्डी क्षेत्र में मण्डी कृत्यकारी के रूप में काम नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात ऐसी कृषि उपज के निम्नलिखित विक्रय और क्रय को लागू नहीं होगी,—

- (i) जहाँ विक्रय उत्पादक द्वारा स्वयं किसी व्यक्ति को, उसके घरेलू उपयोग के लिए विहित सीमा तक की मात्रा में किया गया है;
- (ii) जिसका क्रय और विक्रय, छोटे व्यापारी जो विहित किया जाए, द्वारा किया गया है; और
- (iii) जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के व्याहारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम, स्टेट कॉमडिटिज ट्रेडिंग कारपोरेशन या किसी अन्य अभिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था से लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये किया गया है।

28. (1) उप-धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, समस्त अधिसूचित कृषि उपज का, साधारणतः मण्डी प्रांगण, उप-मण्डी प्रांगण या अनुज्ञप्ति धारक के प्राइवेट प्रांगणों में विक्रय किया जाएगा : मण्डी में अधिसूचित कृषि उपज की बिक्री।

परन्तु यह कि अधिसूचित कृषि उपज का इस अधिनियम की धारा 22 और 23 के अधीन, इस निमित्त अनुज्ञात अनुज्ञप्ति धारक को किसी अन्य स्थान पर विक्रय किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि संविदा खेती के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज को मण्डी प्रांगण, उप मण्डी प्रांगण और प्राइवेट प्रांगण में लाना आवश्यक नहीं होगा और ऐसी कृषि उपज का किसान के खेतों से संविदा खेती, प्रायोजक को सीधे तौर पर विक्रय किया जा सकेगा।

(2) मण्डी प्रांगण में विक्रय के लिए लाई गई अधिसूचित कृषि उपज का मूल्य, खुली नीलामी द्वारा या किसी अन्य पारदर्शी प्रणाली, जैसी विहित की जाए, द्वारा तय किया जाएगा, और किसी भी मददे जो भी हो, करार पाई गई कीमत से कोई कटौती, विक्रेता से नहीं की जाएगी :

परन्तु प्राइवेट प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज की कीमत ऐसी रीति में तय की जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि उपज का तोल या माप या गणना, ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसी रीति में की जाएगी जैसी, उप-विधियों में उपबन्धित की जाए।

अध्याय-4

समिति की स्थापना, गठन, शक्ति और कृत्य

समिति की
स्थापना।

29. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के लिए एक कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना करेगी और इसके मुख्यालय को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक समिति शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद ला सकेगी या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा और जो धारा 78 के उपबन्धों के अध्यधीन, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन और धारण करने और ऐसी किसी सम्पत्ति जो उसमें निहित हो गई है या उस द्वारा अर्जित की गई है, को पट्टे पर देने, विक्रय करने या अन्यथा अन्तरण करने और संविदा करने तथा उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त कार्य करने के लिए सक्षम होगी, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है :

परन्तु कोई समिति किसी स्थावर सम्पत्ति को, समिति के सदस्यों के तीन चौथाई से अन्यून बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में पारित संकल्प के और बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाए, स्थाई रूप से अन्तरित नहीं करेगी।

समिति का
गठन।

30. (1) समिति सोलह सदस्यों से मिल कर बनेगी, जिन में से छः पदेन सदस्य होंगे और दस गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

(2) पदेन सदस्य :—

- (i) उपायुक्त — उपाध्यक्ष;
- (ii) उप-निदेशक कृषि;
- (iii) उप-निदेशक उद्यान;
- (iv) उप-निदेशक पशुपालन;

(v) कृषि विज्ञान केन्द्र का भारसाधक; और

(vi) समिति का सचिव।

(3) गैर-सरकारी सदस्य, भरी जाने वाली रिक्तियों की दुगुनी संख्या के बराबर, सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा दिए गए नामों की सूची में से, राज्य सरकार द्वारा, नीचे उपबन्धित रीति में नियुक्त किए जाएंगे:-

(i) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के उत्पादकों में से नौ गैर-सरकारी सदस्य; और

(ii) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से, धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों में से, एक गैर-सरकारी सदस्य।

31. (1) धारा 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।

समिति के सदस्यों की पदावधि।

(2) समिति के पदेन सदस्य की पदावधि समाप्त हो जायेगी, जैसे ही वह उस पद को छोड़ देता है जिसके फलस्वरूप उसका नामनिर्देशन किया गया था।

32. कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य बनने के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है।

समिति के सदस्यों की निरर्हताएं।

33. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि के दौरान, किसी भी समय हटा सकेगी, यदि ऐसा सदस्य उसकी राय में, अवचार या कर्तव्य की अवहेलना का दोषी है या वह ऐसी अर्हताएं से विहीन हो गया जिनके आधार पर उसे नियुक्त किया गया था :

समिति के सदस्यों का हटाया जाना।

परन्तु यह कि इससे पूर्व कि बोर्ड इस धारा के अधीन किसी सदस्य का हटाया जाना अधिसूचित करे सम्बन्धित सदस्य को, उसके प्रस्तावित हटाए जाने के कारण संसूचित करेगा और उसे लिखित रूप

में स्पष्टीकरण निविदत्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि मृत्यु, त्याग पत्र, सेवा-निवृत्ति, स्थानांतरण या हटाए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न गैर-सरकारी सदस्य की कोई रिक्ति यथासाध्य शीघ्रता से भरी जाएगी।

समिति की बैठक।

34. (1) समिति अपने कारबार के संव्यवहार के लिए तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी परन्तु समिति, विशेष परिस्थितियों में मण्डी क्षेत्र में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर बैठक कर सकेगी।

(2) अध्यक्ष, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि वह अनुपस्थित है, तो उपाध्यक्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो बैठक में उपस्थित ऐसा कोई एक सदस्य, जो उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यक्षीन, समिति अपने कारबार का संचालन, जैसा विहित किया जाए, करेगी।

समिति के अध्यक्ष का निर्वाचन।

35. प्रत्येक समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेगी :

परन्तु अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए केवल समिति के उत्पादक सदस्य ही पात्र होंगे।

समिति के अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र।

36. (1) समिति का अध्यक्ष और कोई गैर-सरकारी सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में सम्बोधित करते हुए अपने पद से किसी भी समय त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसे अध्यक्ष या गैर-सरकारी सदस्य का स्थान, (पद) उसके त्याग पत्र की स्वीकृति की तारीख से रिक्त हो जाएगा।

(2) अध्यक्ष के कार्यालय में, मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण या अन्यथा किसी रिक्ति के दौरान, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी

बात के होते हुए भी, समिति का ऐसा उत्पादक सदस्य, जिसे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का अनुपालन तब तक करेगा, जब तक कि अध्यक्ष सम्यक् रूप से निर्वाचित नहीं हो जाता है।

37. (1) अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव उप-धारा (2) के अधीन प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में लाया जाएगा और यदि प्रस्ताव समिति के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो वह समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा।

समिति के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए समिति की बैठक, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, की जाएगी।

(3) अध्यक्ष, बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा परन्तु ऐसी बैठक की अध्यक्षता, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे इस द्वारा प्राधिकृत किया जाए, तथापि, अध्यक्ष को बोलने का और अन्यथा बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा।

(4) यदि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या यदि गणपूर्ति न होने के कारण बैठक नहीं होती है, तो उसी अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के किसी पश्चात्पूर्ति प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि ऐसी नियत बैठक की तारीख से छः मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता।

38. समिति या उसका किसी उप-समिति या समिति के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या सचिव के रूप में कार्य कर रहे, किसी व्यक्ति का कोई भी कार्य, ऐसी समिति, उप-समिति, सदस्यों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीठासीन प्राधिकारी या समिति के सचिव की नियुक्ति या संविधान में किसी त्रुटि के कारण या इस आधार पर कि वे सब या उनमें से कोई ऐसे पद के लिए निरर्हित किया गया था/किए गए थे या समिति या उप-समिति की बैठक आयोजित करने के आशय का सम्यक् रूप से औपचारिक नोटिस नहीं दिया गया था, या समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सचिव या ऐसी समिति या उप-समिति के सदस्य

समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना।

के पद में किसी रिक्ति की अवधि के दौरान किया गया ऐसा कार्य या किसी अन्य अशक्तता, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करें, के कारण, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

समिति की
शक्तियाँ और
कृत्य।

39. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समिति,—

(क) अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गए नियमों और उप-विधियों के उपबन्धों को प्रवृत्त कर सकेगी;

(ख) मण्डी क्षेत्र में मण्डी स्थापित कर सकेगी और सम्बद्ध कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भण्डारकरण, तोल और प्रसंस्करण के सम्बन्ध में आने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसी प्रसुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगी, जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्दिष्ट करे;

(ग) ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी, जो मण्डी के अधीक्षण, निर्देशन और नियन्त्रण के सम्बन्ध में या मण्डी क्षेत्र में किसी स्थान में कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के लिए और उपर्युक्त मामलों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये, अपेक्षित हों, और उस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी, जैसी इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उपबन्धित की जाएं।

(घ) समस्त ऐसे अन्य कार्य कर सकेगी, जो मूल्यांकन प्रणाली और मण्डी क्षेत्र में हो रहे संव्यवहारों में पूर्ण पारदर्शिता लाएं।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति,—

(i) मण्डी क्षेत्र के भीतर मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण का अनुरक्षण और प्रबन्ध कर सकेगी;

- (ii) विपणन के लिए आवश्यक प्रसुविधाओं का उपबन्ध कर सकेगी और मण्डी क्षेत्र में मण्डी प्रांगणों के भीतर और प्रांगणों से बाहर और उप-मण्डी प्रांगणों के भीतर या उप मण्डी प्रांगणों के बाहर कृषि उपज के परिवहन को सुकर बना सकेगी;
- (iii) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या समिति की उप-विधियों में अधिकथित उपबंधों और प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज की नीलामी को विनियमित, संचालित और पर्यवेक्षित कर सकेगी;
- (iv) विक्रयों, तोल, परिदान, संदाय के करारों का कार्यान्वित, और प्रवर्तित या रद्द करने और विहित रीति में अधिसूचित कृषि उपज की मण्डी से सम्बन्धित, सभी अन्य विषयों को विनियमित कर सकेगी;
- (v) विक्रेता और क्रेता के मध्य, अधिसूचित कृषि उपज के विपणन और उसके आनुषंगिक समस्त मामलों से सहबद्ध किसी प्रकार के संव्यवहार पर उठे समस्त विवादों के निपटारे के लिए उपबंध कर सकेगी;
- (vi) अधिसूचित कृषि उपज के अपमिश्रण को रोकने के लिए समस्त संभव कदम उठा सकेगी;
- (vii) मण्डी प्रांगणों या उप-प्रांगणों में किए जाने वाले संव्यवहारों की बाबत माल के तोलने और परिवहन करने के लिए तोलने वालों और हमालों का रजिस्ट्रीकरण कर सकेगी;
- (viii) मण्डियों के प्रबंधन में लोक-प्राइवेट भागीदारी की स्थापना और उन्नयन कर सकेगी;
- (ix) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों और संचलन की बाबत इसके क्षेत्र में विस्तार कार्यकलापों जैसे कि जानकारी इकट्ठा करने, अनुसंधान और प्रसार कार्यान्वित करने के लिए लोक-प्राइवेट भागीदारी में अभिवृद्धि कर सकेगी;
- (x) दरों, प्रमारों, फीसों और अन्य धन राशियों जिनके लिए

समिति हकदार है, को उद्गृहीत, ले, वसूल या प्राप्त कर सकेगी;

- (xi) मण्डी में आने वाले व्यक्तियों, यानों के प्रवेश और यातायात को मण्डी प्रांगण या उप-मण्डी प्रांगण में विनियमित कर सकेगी;
- (xii) इस अधिनियम (धारा 27 के सिवाय) या नियमों और तदधीन बनाई गई उप-विधियों के अधीन किए गए अपराधों का शमन कर सकेगी;
- (xiii) अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित कर सकेगी और किसी जंगम और स्थावर सम्पत्ति का व्ययन कर सकेगी;
- (xiv) किसी वाद, अभियोजन, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् संस्थित और प्रतिरक्षण कर सकेगी, तथा ऐसे वाद, कार्रवाई, कार्यवाही, आवेदन या माध्यस्थम् में समझौता कर सकेगी;
- (xv) प्रत्येक मुख्य मण्डी प्रांगण और उप-मण्डी प्रांगण में, एक बाट और माप मानक सैट रख सकेगी, जिससे तोल और माप की जांच की जा सकेगी;
- (xvi) मण्डी क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले मापमानों, बाटों और मापों तथा लेखा बहियों तथा मण्डी कृत्यकारियों द्वारा, अनुरक्षित अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण और सत्यापन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, कर सकेगी;
- (xvii) जानवरों, पशुओं, पक्षियों, जिनका मण्डी प्रांगण या मण्डी क्षेत्र में क्रय या विक्रय किया जाता है, इत्यादि की बाबत पशु चिकित्सक से उपयुक्तता (स्वास्थ्य) प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की व्यवस्था कर सकेगी;

- (xviii) विभिन्न माध्यमों जैसे कि इश्तहार, पेम्पलैटों, विज्ञापनों, सिनेमा सलाइडज, फिल्म प्रदर्शनों, समूह बैठकों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि या अधिक प्रभावी या आवश्यक समझे गए किसी अन्य साधन के माध्यम से मण्डी प्रांगण इत्यादि में उपबन्धित विनियमन, संव्यवहार प्रणाली, सुविधाओं के लाभों के बारे में प्रचार कर सकेगी;
- (xix) विक्रेता को, मण्डी प्रांगण में किए गए संव्यवहार के बारे में उसी दिन में संदाय सुनिश्चित कर सकेगी और व्यतिक्रम में सम्बद्ध व्यक्ति की अन्य सम्पत्ति सहित प्रश्नगत कृषि उपज का अभिग्रहण कर सकेगी और उसके पुनः विक्रय की व्यवस्था कर सकेगी, और हानि की दशा में हानियों की वसूली के लिए प्रमारों सहित, यदि कोई हो उसे मूल क्रेता से वसूल कर सकेगी और विक्रेता को कृषि उपज की कीमत संदाय कर सकेगी;
- (xx) तुलाई करने वाले व्यक्ति और हमालों की बाबत प्रमारों की वसूली कर सकेगी और तुलाई करने वाले व्यक्ति और हमालों में उसका वितरण कर सकेगी, यदि, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता ने उन्हें संदत्त न किया हो;
- (xxi) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादन, विक्रय, मण्डारकरण, प्रसंस्करण कीमतों और संचलन के बारे में सूचना एकत्रित और अनुरक्षित कर सकेगी और बोर्ड द्वारा यथा निदेशित ऐसी सूचना का प्रसार कर सकेगी;
- (xxii) मण्डी में स्थिरता बनाए रखने की दृष्टि से यह सुनिश्चित करने के उपयुक्त उपाय कर सकेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य से परे कृषि उपज न खरीदें और विक्रेताओं को उपज के व्ययन के जोखिम से बचा सकेगी; और क्रेताओं की सामर्थ्य के अनुसार बैंक गारंटी के रूप में नकद में

आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगी; और

(xxiii) कृषि उपज में मूल्य परिवर्धन के लिए क्रियाकलापों सहित कृषि प्रसंस्करण का उन्नयन कर सकेगी और जिम्मा ले सकेगी।

(3) बोर्ड की पूर्व मंजूरी से समिति निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा ले सकेगी :—

- (i) मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के विपणन को सुकर बनाने के लिए मण्डी क्षेत्र में सड़कों, गोदामों, रज्जु मार्गों और अन्य अवसंरचनाओं का सन्निर्माण और इस प्रयोजन के लिए बोर्ड को निधियां देना;
- (ii) कृषकों को कृषि उपज के संचयन के लिए किराए पर मण्डारकरण की सुविधा की व्यवस्था करना;
- (iii) ई-ट्रेडिंग अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए समिति नियामक पद्धति की स्थापना, अवसंरचना का सृजन और उसके लिए आवश्यक अन्य क्रियाकलापों का जिम्मा ले सकेगी और इनके लिए आवश्यक कदम उठा सकेगी;
- (iv) पर पहुँच के आँकड़े और विक्रय के लिए मण्डी क्षेत्र में स्तर अनुसार लाई गई कृषि उपज की दरों, जैसी विहित की जाए, का समय-समय अनुरक्षण और परिचालन करना।

मण्डी
कृत्यकारियों
का
रजिस्ट्रीकरण।

40. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो, अधिसूचित कृषि उपज की बाबत मण्डी क्षेत्र में व्यापारी, कमीशन अभिकर्ता, तोलने वाले, हमाल, सर्वेक्षक, भाण्डागारपाल, संविदा खेती प्रायोजक, प्रसंस्करण कारखाने का स्वामी या अधिमोगी या कोई अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में परिचालन की वांछा रखता है, तो वह, समिति के सचिव को रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाए, आवेदन करेगा। समिति का सचिव, समिति के पूर्व

अनुमोदन से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला प्राधिकारी होगा :

परन्तु कोई व्यक्ति मण्डी प्रांगण/उप-मण्डी प्रांगण में रजिस्ट्रीकृत हुए बिना भी दिन प्रतिदिन के आधार पर कृषि उपज खरीद सकेगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति जो, एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में किसी भी अधिसूचित कृषि उपज व्यापार या संव्यवहार या व्याहार करने की वांछा रखता है, तो वह स्वयं को, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक से तत्सम्बन्धी कृत्य के लिए रजिस्ट्रीकृत करवाएगा।

(2) कोई भी दलाल, व्यापारी, तोलने वाला, सर्वेक्षक, गोदाम रक्षक या अन्य कृत्यकारी जब तक कि सम्यक् रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तब तक इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज की बाबत अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में अपना व्यवसाय नहीं करेगा।

(3) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी फीस के साथ किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

(4) समिति रजिस्ट्रीकरण कर सकेगी या रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगी या निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को नामंजूर कर सकेगी या रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगी :—

- (i) यदि आवेदक अवयस्क है; या
- (ii) यदि आवेदक व्यतिक्रमी घोषित किया गया है; या
- (iii) यदि आवेदक को, इस अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन दोषी पाया गया हो।

41. (1) प्रत्येक समिति का एक सचिव होगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समिति के सचिव के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के अनुसार, नियुक्त किया जाएगा।

समिति के सचिव की नियुक्ति।

(2) समिति का सचिव समिति का पदेन सचिव होगा और समिति के सभी अभिलेखों और संपत्तियों का अभिरक्षक होगा।

उप-समितियों
की नियुक्ति
और
शक्तियों का
प्रत्यायोजन।

42. समिति, किसी भी कार्य के संचालन या किसी विषय पर रिपोर्ट के लिए उप-समिति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी उप-समिति को ऐसी शक्तियां या कर्तव्य, जैसे यह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

समिति के
सचिव की
शक्तियां
और
कर्तव्य।

43. समिति का सचिव इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा, अर्थात् :—

- (i) समिति और उप-समितियों, की बैठकों, यदि कोई हो, का आयोजन करना और उनकी बैठकों के कार्यवृत्त रखना;
- (ii) समिति और उप-समिति की बैठकों में उपस्थित होना और चर्चा में भाग लेना;
- (iii) समिति और उप-समिति के संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना और अगली बैठक में समिति के ऐसे संकल्प के अनुसरण में की गई सभी कार्रवाइयों की रिपोर्ट देना;
- (iv) समिति के बजट प्रस्ताव को तैयार करना;
- (v) समिति को, निम्नलिखित सूचनाओं सहित, ऐसी विवरणियां, विवरण, प्राक्कलन, आंकड़े और रिपोर्टें देना, जैसी समिति समय-समय पर अपेक्षा करे :—
 - (क) सदस्यों या कर्मचारीवृन्द और मण्डी कृत्यकारियों और अन्यो पर अधिरोपित जुर्माने और शास्तियों और उनके विरुद्ध की गई कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई;
 - (ख) व्यापारियों द्वारा अधि-व्यापार (ओवर ट्रेडिंग);

- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम, नियमों, उप विधियों या स्थायी आदेशों, यदि कोई हो, के उल्लंघन के बारे में;
- (घ) बोर्ड के प्रबंध निदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति के निलम्बन या रद्दकरण के बारे में;
- (ङ) समिति के प्रशासन और विपणन के विनियमन के बारे में;
- (vi) समिति या उप-समिति के कारबार के सव्यवहार के लिए यथा आवश्यक बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को समिति के समक्ष प्रस्तुत करना, और जब कभी भी समिति द्वारा ऐसा करने को कहा जाए;
- (vii) समिति के सभी अधिकारियों और सेवकों के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखना;
- (viii) समिति द्वारा उद्ग्रहणीय या को देय फीसों और अन्य धन का संग्रहण;
- (ix) समिति में जमा किए गए या की ओर से प्राप्त किए गए समस्त धन के लिए उत्तरदायी होना;
- (x) समिति द्वारा विधिपूर्वक संदेय समस्त धन का संवितरण करना;
- (xi) समिति की निधि का प्रवर्तन, अनुरक्षण और संव्यवहार करना;
- (xii) बोर्ड के प्रबंध निदेशक को, समिति की निधि या संपत्ति के कपट, गबन, चोरी या हानि के बारे में यथाशक्यशीघ्र रिपोर्ट करना; और

- (xiii) समिति की ओर से चलाए जाने वाले अभियोजनों के बारे में परिवाद (शिकायतें) करना और समिति की ओर से सिविल या अपराधिक कार्यवाहियों का संचालन करना।

अध्याय-5

बोर्ड और समिति का वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

मण्डी फीस
का
उद्ग्रहण।

44. प्रत्येक समिति मूल्यानुसार प्रत्येक सौ रुपये पर दो रुपये से अनधिक दर पर मण्डी फीस, निम्नलिखित के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उद्ग्रहीत, प्रभारित और संग्रहीत करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए,—

- (i) अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय और क्रय पर, चाहे राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो; और
- (ii) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे प्रसंस्करण के लिए, राज्य के भीतर से लाई गई हो या राज्य के बाहर से मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो।

एकल स्थान
उद्ग्रहण।

45. (1) धारा 44 में विनिर्दिष्ट मण्डी फीस, राज्य के भीतर किसी भी मण्डी क्षेत्र में, दूसरी बार उद्ग्रहीत नहीं की जाएगी; परन्तु यदि उस कृषि उपज पर राज्य की किसी मण्डी क्षेत्र में मण्डी फीस पहले ही संदत्त की जा चुकी है और इस संदर्भ में सम्बद्ध व्यक्ति द्वारा सूचना दे दी गई हो कि मण्डी फीस का संदाय राज्य की अन्य मण्डी में पहले ही किया जा चुका है।

(2) मण्डी क्षेत्र में, वाणिज्य संव्यवहार या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर, मण्डी फीस यथास्थिति, क्रेता या परिष्कर्ता द्वारा समिति के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर, परन्तु ऐसी कृषि उपज के मण्डी क्षेत्र से बाहर विक्रय या पुनः विक्रय या प्रसंस्करण या निर्यात से पहले, जमा की जाएगी।

(3) किसी अधिसूचित कृषि उपज के, ऐसी उपज पर संदेय मण्डी फीस के संदाय के बिना, क्षेत्र से बाहर प्रसंस्करण, विक्रय या पुनः

विक्रय या प्रेषण के पाए जाने की दशा में, मण्डी फीस, यथास्थिति, प्रसंस्कृत उपज के मण्डी मूल्य या कृषि उपज के मूल्य से पांच गुणा मण्डी फीस उद्गृहीत और वसूल की जाएगी।

46. (1) बोर्ड द्वारा या की ओर से प्राप्त किया गया समस्त विपणन धन, विपणन विकास निधि के नाम से ज्ञात निधि में जमा किया जाएगा। विकास निधि।

(2) बोर्ड द्वारा किए गए सभी संदाय, उक्त निधि में से चुकाए जाएंगे।

(3) बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित से,—

(i) किसी अन्य अभिकरण से, या

(ii) इसमें निहित किसी सम्पत्ति के प्राधिकार पर या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन इसे प्रोद्भूत होने वाली इसकी भविष्य में आय के भाग की प्रतिभूति पर डिबेन्चर जारी कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा, विपणन विकास निधि का उपयोग या तो स्वयं या पब्लिक—प्राईवेट भागीदारी के माध्यम से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को न्यस्त कृत्यों के निर्वहन के लिए किया जाएगा। इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विपणन विकास निधि का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकेगा :—

(i) बोर्ड के प्रशासनिक व्यय का संदाय;

(ii) बोर्ड के कर्मचारियों, अध्यक्ष और इसके सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते;

(iii) बोर्ड द्वारा नियोजित व्यक्तियों के वेतन, छुट्टी भत्ते, उपदान, अनुकम्पा भत्ते, कर्तव्यारूढ़ होने पर हुई दुर्घटना

के परिणामस्वरूप क्षति या मृत्यु के लिए प्रतिकर, चिकित्सा सहायता, पेंशन या भविष्य निधि और सैकेन्डमेंट पर सरकारी सेवकों को छुट्टी और पेंशन अभिदाय का संदाय;

- (iv) बोर्ड द्वारा उपगत किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति करना;
- (v) वित्तीय रूप से कमजोर समितियों को यथा विहित निबन्धनों और शर्तों पर ऋण और अनुदान के रूप में सहायता देना;
- (vi) कृषि उपज के विपणन से सम्बन्धित मामलों का प्रचार और प्रसार करना;
- (vii) समिति और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा कृषकों को भी प्रशिक्षण देना;
- (viii) विपणन विस्तार के क्रियाकलापों और ई-ट्रेडिंग के व्ययों की पूर्ति करना;
- (ix) विपणन के विकास के लिए कर्मशालाएं, सेमीनार, प्रदर्शनियां इत्यादि का आयोजन और व्यवस्था करना;
- (x) बोर्ड के कार्यालय का अनुरक्षण और इसके कार्यालय भवनों, विश्राम गृहों और कर्मचारियों के आवास गृहों का सन्निर्माण और मरम्मत;
- (xi) राज्य में विपणन के विनियमन का सामान्य सुधार;
- (xii) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम;
- (xiii) बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा में उपगत व्यय;

- (xiv) कार्यों के निष्पादन सहित समितियों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था करना;
- (xv) मण्डी सर्वेक्षण और अनुसन्धान, श्रेणीकरण और मानकीकरण तथा कृषि उपज और अन्य सहबद्ध विषयों का गुणवत्ता प्रमाणीकरण करना;
- (xvi) कृषि उपज का श्रेणीकरण और मानकीकरण;
- (xvii) मण्डी दरों का संग्रहण और समाचारों का प्रसार करना;
- (xviii) कृषि उपज का बेहतर विपणन; और
- (xix) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य प्रयोजन, जिसे बोर्ड, समितियों के सामान्य हितों, राष्ट्रीय या लोक हित की अभिवृद्धि के लिए प्रकल्पित किया गया हो।

47. (1) बोर्ड द्वारा, आगामी वर्ष के लिए बोर्ड की वार्षिक आय और व्यय का प्राक्कलन तैयार किया जाएगा और प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह के उपरान्त राज्य सरकार को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा बजट की मंजूरी पर बोर्ड को इसके प्रचालन की शक्ति होगी।

बोर्ड का वार्षिक बजट।

(2) राज्य सरकार बजट को, उसकी प्राप्ति की तारीख से दो मास के भीतर, मंजूर करेगी और उसे वापस करेगी। यदि इसके प्रस्तुत करने की तारीख से दो मास के भीतर यह प्राप्त नहीं होता है, तो इसे मंजूर किया गया समझा जाएगा।

48. (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों के सही और पूर्ण लेखे देकर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अर्पित करेगा।

बोर्ड के लेखे, लेखा परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट।

(2) बोर्ड के लेखों की, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के परीक्षक

द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे राज्य सरकार निदेशित करे, प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा किया जाएगा।

(3) बोर्ड के लेखों की यथाशक्य शीघ्र लेखा परीक्षा होने पर, बोर्ड लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति राज्य सरकार को भेजेगा।

(4) बोर्ड द्वारा उप-धारा (3) के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट, प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् राज्य सरकार उक्त रिपोर्टों को राज्य विधान सभा के पटल पर रखवाएगी :

परन्तु यह कि जब रिपोर्टें बजट सत्र में रखी जानी हों तो यह उक्त सत्र की प्रथम बैठक में सदन के पटल पर रखी जाएंगी :

परन्तु यह और कि वित्तीय वर्ष, जिससे रिपोर्टें सम्बन्धित है, के समाप्त होने और रिपोर्टों को रखने की मध्यवर्ती अवधि, नौ मास से अधिक नहीं होगी।

समिति की
निधि।

49. (1) उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय समिति द्वारा प्राप्त समस्त धन "समिति निधि" के नाम से ज्ञात निधि में संदत्त किया जाएगा और इस अधिनियम के अधीन या के प्रयोजनों के लिए समिति द्वारा उपगत समस्त व्यय, उक्त निधि में से चुकाए जाएंगे। ऐसे व्यय की पूर्ति किए जाने के पश्चात् समिति के पास बचा हुआ कोई अतिशेष, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, विनिहित किया जाएगा।

(2) समिति द्वारा माध्यस्थम् फीस के रूप में या वाद से सम्बन्धित माध्यस्थम् कार्यवाहियों में लागतों के लिए प्रतिभूति के रूप में या समिति द्वारा प्रत्याभूति जमा, भविष्य निधि के अमिदाय के रूप में प्राप्त किया गया कोई धन या किसी अधिसूचित कृषि उपज की बाबत संदाय के लिए या समिति द्वारा संदेय अन्य प्रमारों या नियमों या उप-विधियों में यथा उपबन्धित के लिए समिति द्वारा प्राप्त किया गया ऐसा अन्य धन, समिति निधि का भाग नहीं होगा और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जैसी विहित की जाए।

(3) प्रत्येक समिति अपनी निधि में से वर्ष के दौरान धारा 44 के अधीन संगृहीत कुल मण्डी फीस का पच्चीस प्रतिशत बोर्ड की स्थापना के व्ययों को पूरा करने और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को समनुदेशित कृत्यों के निष्पादन में उपगत व्ययों के लिए, बोर्ड को संदत्त करेगी।

(4) इस धारा में विनिर्दिष्ट और समिति की निधि का भाग रूप, समस्त धन और प्राप्तियां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या राष्ट्रीय कम्प्यूटरीकृत तंत्र से युक्त किसी अन्य बैंक या हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में जमा की जाएंगी।

(5) समिति का सचिव कार्यालय का प्रमुख होगा और वह ऐसी वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अधीन कार्यालय के प्रमुख को प्रदत्त हैं।

50. (1) प्रत्येक समिति आगामी वर्ष के लिए ऐसी रीति में और ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर, जैसी विहित की जाए अपनी आय और व्यय का बजट तैयार और पारित करेगी और उसे बोर्ड के प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगी और प्रबंध निदेशक अनुमोदन के लिए उसे बोर्ड के समक्ष रखेगा। बोर्ड बजट को, इसके प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर, उपांतरण सहित या बिना उपांतरण के अनुमोदित करेगा। यदि बजट को प्रबंध निदेशक द्वारा दो मास के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो इसे अनुमोदित किया गया समझा जाएगा।

समिति के बजट की तैयारी और मंजूरी।

(2) समिति वर्ष के दौरान, किसी भी समय जिस के लिए कोई बजट मंजूर किया गया है, पुनरीक्षित या प्रतिपूरक बजट, उसी रीति में जैसे कि यह मूल बजट था पारित करवाएंगी या मंजूर करवाएंगी।

(3) समिति द्वारा किसी मद पर कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा यदि उसका मंजूर बजट में कोई उपबंध नहीं है जब तक कि इसकी पूर्ति किसी अन्य शीर्ष के अधीन बचत से पुनर्विनियोग द्वारा न की जा सके। पुनर्विनियोग के लिए मंजूरी बोर्ड से अभिप्राप्त की जा सकेगी, परन्तु एक मुख्यशीर्ष के अधीन लघुशीर्षों से पुनर्विनियोग की दशा में, पुनर्विनियोग के लिए मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।

प्रयोजन
जिसके लिए
समिति की
निधि का
व्यय किया
जा सकेगा।

51. धारा 49 के उपबंधों के अध्वधीन, समिति, इस अधिनियम के अधीन इसे न्यस्त कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, समिति निधि का प्रयोग कर सकेगी। इस उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा, अर्थात:-

- (i) मण्डी के लिए स्थल या स्थलों का अर्जन;
- (ii) मण्डी प्रांगण की स्थापना, अनुरक्षण और सुधार;
- (iii) मण्डी प्रांगण के प्रयोजन के लिए और मण्डी प्रांगण का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिए आवश्यक भवनों का सन्निर्माण और मरम्मत;
- (iv) मानक-भार और माप का अनुरक्षण;
- (v) समिति के अधिकारियों और सेवकों इत्यादि की भविष्य निधि अभिदायों, पेन्शन और उपदान हेतु संदायों, अंशदानों सहित स्थापना प्रमारों की पूर्ति;
- (vi) समिति के कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम;
- (vii) उन ऋणों पर ब्याज का संदाय जो मण्डी के प्रयोजनार्थ के लिए जाएं और उन ऋणों की बाबत निक्षेप निधि के उपबंध;
- (viii) फसल आंकड़ों और कृषि उपज की बाबत विपणन से सम्बन्धित जानकारी का संग्रहण करना और प्रसार करना;
- (ix) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा में उपगत व्यय और कार्यालयों के अनुरक्षण में उपगत व्यय;
- (x) समिति के अध्यक्ष और अन्य गैर सरकारी सदस्यों और समिति के कर्मचारियों के मानदेय और यात्रा भत्ते का संदाय जो विहित किया जाए;
- (xi) विपणन विकास निधि में अभिदाय;
- (xii) परिवहन सहित कृषि विपणन के विकास के लिए किसी स्कीम हेतु अभिदाय;
- (xiii) मण्डी क्षेत्र में कृषक के लिए श्रेणीकरण, मानकीकरण

गुणवता प्रमाणीकरण सेवाएं और ससूचना जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाना;

- (xiv) कृषि उपज के विपणन में अनुसन्धान और विकास, विस्तार तथा किसानों के प्रशिक्षण पर उपगत किए जाने वाले व्यय;
- (xv) कृषि उपज के, अन्य अभिकरणों, राज्य, केन्द्रीय और अन्य के साथ सहयोजन में करस्थम् विक्रय को रोकना;
- (xvi) सहकारी विपणन का पोषण करना और सहकारी विपणन सोसाइटियों को उपज के विशेषतया लघु एवं सीमान्त किसानों से सम्बन्धित उपज के, उपापन और लाभदायी निपटान में सहायता करना;
- (xvii) स्वयं या लोक-प्राइवेट सांझेदारी द्वारा अवसंरचना के सृजन और उन्नयन द्वारा तथा कृषि उपज, कोल्ड-स्टोरेज, प्रीकूलिंग प्रसुविधाओं, पैक गृहों और आधुनिक मण्डी प्रणाली के विकास के लिए ऐसी सभी अवसंरचना का पश्च-सलवन (पोस्ट हारविस्ट) हथालन;
- (xviii) समिति द्वारा उपगत किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति;
- (xix) समिति के कर्मचारीवृन्द के प्रशिक्षण और कुशलतावृद्धि पर; और
- (xx) बोर्ड की पूर्व मंजूरी के साथ किसी अन्य प्रयोजन, जो समिति या अधिसूचित मण्डी क्षेत्र के सामान्य हित में अभिवृद्धि के लिए परिकलित है या कोई अन्य प्रयोजन जो राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए की परिकलित हो।

52. (1) समिति, बोर्ड की पूर्व मंजूरी से उन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए जिनके लिए यह स्थापित की गई है, समिति में निहित और उससे संबंधित किसी सम्पत्ति और इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा उदगृहीत किन्हीं फीसों की प्रतिमूति पर, अपेक्षित धन राशि उधार ले सकेगी। उधार लेने की शक्ति।

(2) समिति, मण्डी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि, भवन और उपकरणों पर आरम्भिक व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकार या बोर्ड या अन्य समितियों या वित्तीय संस्थाओं, से ऐसी शर्तों पर जो विहित की जाएं, ऋण ले सकेगी।

अध्याय-6

नियन्त्रण

मण्डियों का
निरीक्षण और
समिति के
कार्यकलापों
की जांच।

53. (1) बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक,—

- (क) समिति के लेखों और कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा;
- (ख) समिति के कार्यकलापों की जांच कर सकेगा;
- (ग) समिति की विवरणी, विवरण, लेख या रिपोर्ट मंगवा सकेगा जिनकी वह ऐसी समिति से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे;
- (घ) समिति से निम्नलिखित पर विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा—
 - (i) अवैद्यता, असमीचीनता, अनौचित्य, जो उसे ऐसी समिति के द्वारा या की ओर से किसी बात के, जो की जानी है या की जा रही है, करने के लिए, उसे, विद्यमान प्रतीत होती है, के आधार पर कोई आक्षेप करना; या
 - (ii) कोई सूचना जिसे देने के लिए वह दायी है और जो उसे ऐसी समिति द्वारा कतिपय कार्य को करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) जब मण्डी के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाता है या किसी समिति की कार्यवाहियों का धारा 55 के अधीन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा परीक्षण किया जाता है तो ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सभी अन्य अधिकारी तथा सेवक और सदस्य समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, उनके आधिपत्य में ऐसी सूचना जैसी, यथास्थिति, बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक या प्राधिकृत अन्य अधिकारी अपेक्षा करें, प्रस्तुत करेंगे।

(3) उप-धारा (1) के अधीन समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण करने वाले अधिकारी या धारा 54 के अधीन किसी समिति की कार्यवाहियों का परीक्षण करने वाली राज्य सरकार को समिति के अधिकारियों या सदस्यों को बुलाने और हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने और उन्ही साधनों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने को बाध्य करने और की शक्ति होगी और यथासम्भव उसी रीति में जैसे सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपबन्ध किया गया है। जहां बोर्ड के प्रबंध निदेशक को यह विश्वास करने का कारण है कि समिति की बहियों और अभिलेखों में गड़बड़ करने या नष्ट किए जाने की संभावना है या समिति की निधियों या सम्पत्ति के दुर्विनियोग या दुरुपयोजन की संभावना है तो बोर्ड का प्रबंध निदेशक उसके द्वारा सम्यक रूप में प्राधिकृत व्यक्ति को, आदेश जारी करके उसे लिखित में समिति की ऐसी बहियों और अभिलेखों, निधियों और संपत्ति को अभिगृहीत करने तथा कब्जे में लेने के लिए निदेशित कर सकेगा और ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों और संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी समिति का/के अधिकारी उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को करेगा/करेंगे।

54. (1) यथास्थिति, बोर्ड का प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार समिति या स्वप्रेरणा से या इसको किए गए आवेदन पर, यथास्थिति, किसी बोर्ड या समिति की कार्यवाहियां, किए गए किसी विनिश्चय या पारित आदेश की कार्यवाहियों को मंगवाने की शक्ति। वैद्यता या औचित्य के बारे में इसके समाधान के प्रयोजन के लिए और यथास्थिति, समिति या बोर्ड की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में, मंगवा सकेगी और परीक्षण कर सकेगी। यदि किसी मामले में बोर्ड के प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार मंगवाया गया कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियां पुनर्विचार हेतु उपांतरित, बातिल, उलट या विप्रेषित कर दी जानी चाहिए तो यह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे:

परन्तु यह कि, यथास्थिति, बोर्ड के प्रबंध निदेशक या राज्य सरकार को प्रत्येक आवेदन, ऐसे विनिश्चय या आदेश की आवेदक को संसूचना, की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इसके द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए बिना उप-धारा (1) के अधीन ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(2) यथास्थिति, बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक या राज्य सरकार, यथास्थिति, समिति या बोर्ड द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के निष्पादन को, उप-धारा (1) के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग के लम्बित रहते हुए, निलम्बित कर सकेगी।

समिति द्वारा पारित संकल्प या किए गए आदेश के निष्पादन या अतिरिक्त निष्पादन को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति।

55. बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक स्वप्रेरणा से या रिपोर्ट पर या शिकायत की प्राप्ति पर, समिति या इसके अध्यक्ष या इसके किसी अधिकारी या सेवक द्वारा पारित संकल्प या किए गए आदेश के निष्पादन को या अतिरिक्त निष्पादन को आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा संकल्प या आदेश लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, या किसी भी मण्डी क्षेत्र, मुख्य मण्डी प्रांगण या उप-मण्डी प्रांगण में कारबार के दक्षतापूर्ण संचालन को प्रभावित करने वाला है या इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के विरुद्ध है।

हानि, उपघय या दुर्विनियोग आदि के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों का दायित्व।

56. (1) यदि धारा 53 के अधीन जांच या निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि कोई व्यक्ति जो, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के प्रबन्धन से न्यस्त है या था या बोर्ड या समिति का कोई मृतक, मृतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी या राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने उससे संबंधित किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या भाग लेकर, इस अधिनियम, नियमों या तदधीन बनाई गई उप-विधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल किसी प्रयोजन के लिए ऐसी समिति के किसी धन के संदाय या उसकी या उसके नियन्त्रण के अधीन अन्य सम्पत्ति का उपयोजन किया है या इसके लिए निदेश दिया है, या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी या हानि कारित की है या बोर्ड या समिति से सम्बन्धित किसी धन या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोजन या कपटपूर्वक प्रतिधारण किया है, तो बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक स्वप्रेरणा से या आवेदन पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच या तो स्वयं या उस द्वारा इस निमित्त लिखित आदेश

द्वारा, सम्यक् रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा करने का निदेश देगा।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन की गई जांच पर, बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक का समाधान हो जाता है कि इस उप-धारा के अधीन आदेश के लिए ठोस आधार है तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृतक व्यक्ति की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जो उसकी सम्पदा अन्तर्निहित करता है, धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ऐसी दर पर ब्याज सहित प्रतिसंदत्त या प्रत्यावर्तित करने या अभिदाय और लागत या प्रतिकर को उस विस्तार तक संदत्त करने, जिसे बोर्ड का प्रबन्ध निदेशक न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण समझे, की अपेक्षा करते हुए आदेश करेगा:

परन्तु यह कि इस उप-धारा के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है :

परन्तु यह और कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की सम्पत्ति के उस विस्तार तक होगा, जो ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में आई है।

(3) उप-धारा (2) के अधीन किए गए आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, उसको संसूचित किए गए आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और राज्य सरकार का आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा:

परन्तु यह कि परिसीमा की अवधि की संमणना करने में, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है की प्रति प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को, अपवर्जित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेश बोर्ड के सचिव के आवेदन पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय द्वारा, उसी रीति में प्रवर्तित किया जाएगा मानो कि यह उस न्यायालय की डिक्री थी या ऐसे आदेश द्वारा संदत्त किए जाने को निदेशित कोई राशि, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

(5) यदि बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक का शपथपत्र पर, जांच पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी आदेश, जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध पारित किया जा सकेगा, के प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा डालने के आशय से अपनी सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या राज्य से अपनी सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग को हटाने वाला है, तो वह, जब तक कि प्रयाप्त प्रतिभूति नहीं दे दी जाती है, उक्त सम्पत्ति या उसके भाग, जो वह आवश्यक समझे, की सशर्त कुर्की के निदेश देगा और ऐसी कुर्की का वही प्रभाव होगा मानो कि कुर्की सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो।

बोर्ड और
समितियों के
सदस्यों,
अधिकारियों
और सेवकों
का लोक
सेवक होना।

57. बोर्ड और समिति के समस्त सदस्य, अधिकारी और सेवक भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45.

व्यापार भत्तों
का प्रतिषेध।

58. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों द्वारा विहित से अन्यथा कोई भी व्यापार भत्ता या कटौती, अधिसूचित कृषि उपज की बाबत किसी मण्डी क्षेत्र में किए गए किसी संव्यवहार में, किसी भी व्यक्ति द्वारा, प्राप्त नहीं किया जाएगा या नहीं की जाएगी।

लेखे पेश
करने, प्रवेश
करने,
निरीक्षण
करने और
अभिग्रहण
करने का
आदेश देने
की शक्ति।

59. (1) समिति का सचिव या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सशक्त राज्य सरकार या बोर्ड का कोई अन्य अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचित कृषि उपज की किसी किस्म का व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति से अपने समक्ष लेखे और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने या ऐसी किसी कृषि उपज के स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण, मूल्य परिवर्धन या परिदान से सम्बन्धित कोई सूचना देने और ऐसे व्यक्ति द्वारा मण्डी फीस के सदाय से सम्बन्धित कोई अन्य सूचना भी देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के साधारण अनुक्रम में बनाए गए समस्त लेखे और रजिस्टर तथा ऐसी कृषि उपज के स्टॉक या क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण, उसके कब्जे

की ऐसी कृषि उपज का मूल्य परिवर्धन और कार्यालय, स्थापनों, गोदामों, ऐसे व्यक्तियों के जलयानों या यानों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज सभी युक्तियुक्त समयों पर, राज्य सरकार, बोर्ड या समिति के ऐसे अधिकारियों, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए जाएं, के निरीक्षण के लिए अनवरुद्ध रखे जाएंगे।

(3) यदि ऐसे अधिकारी के पास यह संदेह करने के कारण है कि कोई व्यक्ति, उससे इस अधिनियम के अधीन देय, किसी मण्डी फीस का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या किसी व्यक्ति ने, इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय, विक्रय, प्रसंस्करण या मूल्य परिवर्धन किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को लिखित में संसूचित कर ऐसे व्यक्ति के लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज अभिगृहीत कर सकेगा, जैसा आवश्यक हो, और इसके लिए एक रसीद जारी करेगा और उन्हें तब तक के लिए रखे रखेगा जब तक कि वे उनके परीक्षण के लिए या अभियोजन के लिए आवश्यक हों।

(4) उप-धारा (2) या (3) के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी कारबार के किसी स्थान, भाण्डागार गृह, कार्यालय, स्थापन, गोदाम, जलयान या यान में प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा जहां ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति वहां अपने कारबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज या अपने कारबार से सम्बन्धित अधिसूचित कृषि उपज के स्टॉक को रखता है या तत्समय उसने उन्हें रखा है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 (4) से (8) के उपबन्ध यावत्शक्य उप-धारा (4) के अधीन की गई तलाशी को लागू होंगे।

(6) जहां किन्हीं लेखा बहियों का या अन्य दस्तावेजों का किसी स्थान से अभिग्रहण किया गया है और उनमें ऐसी प्रविष्टियां हैं जिनमें मात्रा, कुटेशनज, दरों, प्राप्तियों या धन के संदाय या माल के क्रय या विक्रय की बाबत संदर्भ है तो ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के हाजिर हुए बिना, साक्ष्य में ग्रहण किए

जाएंगे और ऐसी प्रविष्टियाँ विषयों, संव्यवहारों और लेखों, जिनका उनमें अभिलिखित किया जाना तात्पर्यित है, का प्रथमदृष्टतया साक्ष्य होगी।

अनुशिक्षारियों
और
राजिस्ट्रीकृत
कृत्यकारियों
द्वारा वार्षिक
लेखों का
प्रस्तुतिकरण
तथा
निर्धारण।

60. (1) अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करने वाला प्रत्येक व्यापारी, संसाधक, प्राइवेट प्रांगण का स्वत्वधारी, उपभोक्ता कृषक मण्डी का स्वत्वधारी या कमीशन अभिकर्ता प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व समिति के सचिव को, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गए संव्यवहार की एक विवरणी, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) समिति का सचिव उप-धारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई विवरणी को, समिति में सम्यक् रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर आवश्यक परीक्षण और सत्यापन के पश्चात्, स्वीकार या नामजूर करेगा और कृत्यकारी द्वारा संदेय अतिशेष रकम का निर्धारण करेगा और निर्धारित रकम उद्गृहीत करेगा।

(3) समिति के सचिव की कार्यवाहियों से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे नोटिस की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर, समिति को अपील कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, स्वप्रेरणा से या बोर्ड को किए गए आवेदन पर समिति के सचिव द्वारा सत्यापित विवरणी के पुनः सत्यापन की प्रक्रिया, सत्यापन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, आरम्भ कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसा अधिकारी धारा 59 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन अन्तिम होगा।

मण्डी फीस
का निर्धारण।

61. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन लेखे प्रस्तुत करना या सूचना देना अपेक्षित हो, ऐसे लेखे या सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है या जानबूझ कर अधूरे या गलत लेखे या सूचना देता है या उसने अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के समुचित लेखे अनुरक्षित नहीं किए हैं, तो समिति का सचिव स्वप्रेरणा से, समिति के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, धारा 44 के अधीन उद्गृहीत फीस के लिए ऐसे व्यक्ति का निर्धारण करेगा।

62. (1) किसी भी समय जब ऐसा करना अपेक्षित हो, यथास्थिति, बोर्ड द्वारा सशक्त बोर्ड का कोई अधिकारी या समिति द्वारा सशक्त समिति का कोई अधिकारी इस निमित्त, चालक या यान, जलयान या अन्य वाहन के प्रभारी अन्य व्यक्ति को ऐसे जलयान या अन्य वाहन को तब तक रोके रखने के निदेश देगा जब तक युक्ति-युक्त रूप से आवश्यक हो और ऐसे व्यक्ति को यान, जलयान या अन्य वाहन में अन्तर्वस्तु का परीक्षण करना और वहन की गई अधिसूचित कृषि उपज से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करना अनुज्ञात कर सकेगा और वह अपना नाम और पता और यान, जलयान या अन्य वाहन के स्वामी का नाम और पता और ऐसे वाहन, जलयान और अन्य वाहन में वहन की गई अधिसूचित कृषि उपज के स्वामी का नाम और पता ऐसे व्यक्ति को देगा।

यान रोकने
और
निरीक्षण
करने की
शक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति, किसी यान, जलयान या अन्य वाहन में मण्डी क्षेत्र में लाई गई या से बाहर ले जाई गई या बाहर ले जाने के लिए प्रस्तावित किसी अधिसूचित कृषि उपज को अभिगृहीत कर सकेंगे, यदि उनके पास विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन देय फीस या अन्य रकम या ऐसी कृषि उपज की बाबत विक्रेता को संदेय मूल्य संदत्त नहीं किया है।

(3) यदि उप-धारा (1) के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण है कि कोई व्यक्ति धारा 44 के अधीन उससे देय किसी मण्डी फीस के संदाय के अपवचन का प्रत्यन कर रहा है या किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में, मण्डी क्षेत्र में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय या मण्डारण किया है, तो वह कारबार के किसी भी स्थान, भाण्डागारगृह, कार्यालय, स्थापन या गोदाम में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहां उप-धारा (1) के अधीन सशक्त व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति अधिसूचित कृषि उपज का स्टाक रखता है या तत्समय उसने रखा है और मण्डार की गई कृषि उपज का अभिग्रहण कर सकेगा और ऐसी अभिगृहीत अधिसूचित कृषि उपज का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति के पक्ष में अधिहरण किया जा सकेगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100, 457, 458 और 459 के उपबन्ध उप-धारा (1), (2) और (3) के अधीन प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के लिए उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे पुलिस अधिकारी द्वारा सम्पत्ति के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में लागू होते हैं। ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उपरोक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध के विचारण के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तुरन्त की जाएगी।

मण्डी प्रांगण
में अधिक्रमण
हटाने की
शक्ति।

63. (1) राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त सशक्त समिति या बोर्ड के किसी भी अधिकारी या सेवक को मण्डी प्रांगण सहित बोर्ड/या समिति के स्वामित्वाधीन सम्पत्ति पर, किसी भी अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाए जाने का व्यय अधिक्रमण करने वाले द्वारा संदत्त किया जाएगा, यदि वह ऐसे व्यय संदत्त करने में असफल रहता है तो उन्हें उसी रीति में, मू-राजस्व के बकाया के रूप में, वसूल किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सशक्त अधिकारियों की सहायता करने के लिए, समस्त पुलिस अधिकारी, जब भी इस अधिनियम के अधीन उनके कर्तव्यों के पालन में अपेक्षित हो, आबद्ध होंगे और इस प्रयोजन के लिए उनकी ऐसी ही शक्तियां होंगी जैसी अपने सामान्य पुलिस कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी हैं।

(3) उप-धारा (1) के अधीन सशक्त बोर्ड या समिति का कोई अधिकारी या सेवक यदि मण्डी प्रांगण के भीतर अधिक्रमण को हटाने में असफल रहता है, तो वह साधारण कारावास, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मण्डी फीस
से छूट प्रदान
करने की
शक्ति।

64. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिए लाई गई या क्रय की गई या विक्रीत की गई किसी भी कृषि उपज को, पूर्णतः या भागतः मण्डी फीस के संदाय से ऐसी अवधि के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, छूट दे सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी कोई भी अधिसूचना उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व विखण्डित की जा सकेगी और विखण्डन पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रहेगी।

65. जब कभी यह पाया जाता है कि बोर्ड या समिति को देय कोई रकम अवसूलीय है या माफ कर दी जानी चाहिए, या जब कभी बोर्ड या समिति के धन या भण्डारों या अन्य सम्पत्तियों की किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण से या किसी अन्य कारण से कोई हानि होती है और ऐसी सम्पत्ति या धन अवसूलीय पाया जाता है, तो तथ्यों की, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को रिपोर्ट की जाएगी और बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से और समिति बोर्ड के अनुमोदन से रकम या सम्पत्ति का मूल्य, यथास्थिति, अवसूलीय हानि के रूप में बट्टे खाते डालने या माफ करने के आदेश कर सकेगा, परन्तु समिति की दशा में, यदि किसी मामले में देय राशि या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है, तो ऐसा आदेश राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

अवसूलीय फीस इत्यादि को बट्टे खाते डालने की शक्ति।

66. इस अधिनियम या किन्हीं नियमों या तदधीन बनाई गई उप-विधियों के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, माटक के मद्दे या किसी अन्य मद्दे किसी भी व्यक्ति से बोर्ड या समिति को देय कोई राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

बोर्ड या समिति को देय राशियों की वसूली।

67. प्राइवेट मण्डी या उपभोक्ता मण्डी और समिति के मध्य विवाद बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् निपटारा (सुलझाया) जाएगा:

प्राइवेट मण्डी या उपभोक्ता मण्डी और समिति के मध्य विवादों का प्रतिलोभ।

परन्तु इस धारा के अधीन प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

68. (1) धारा 25, 26 या 40 के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, निम्नलिखित को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा—

अपील।

(क) जहां आदेश समिति के सचिव द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, समिति को ;

- (ख) जहां ऐसा आदेश समिति द्वारा पारित किया गया है, वहां आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, बोर्ड को; और
- (ग) जहां ऐसा आदेश बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या बोर्ड द्वारा पारित किया गया है, वहां ऐसे आदेश के पारित किए जाने के तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को।

(2) अपीली प्राधिकारी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह उस आदेश के लिए जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी अवधि के लिए, जैसी वह उचित समझे, स्थगन आदेश दे सकेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश अन्तिम होगा।

सिविल वाद का वर्जन और सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे व्यक्तियों का संरक्षण।

69. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित कोई भी बात या अन्य विधिक कार्यवाहियां राज्य सरकार के किसी अधिकारी या बोर्ड या किसी समिति या बोर्ड या समिति के किसी अधिकारी या सेवक या ऐसे बोर्ड, समिति के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या राज्य सरकार, बोर्ड या समिति के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध न होगी।

नोटिस के अभाव में वाद का वर्जन।

70. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड या किसी समिति के विरुद्ध, जब तक कि आशयित वादी के वाद हेतुक, नाम और निवास स्थान और अनुतोष जिसका वह दावा करता है, का लिखित में कथन करते हुए नोटिस के पश्चात्, दो मास के अवसान तक, जिसे इसके कार्यालय में परिदत्त या छोड़ न दिया गया हो, तब तक कोई वाद संस्थित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ऐसा वाद खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि यह तथाकथित वाद हेतुक के प्रोदभूत होने की तारीख से छः मास के भीतर संस्थित नहीं किया जाता है।

राज्य सरकार की अनुसूची संशोधित करने की शक्ति।

71. (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के अध्याधीन, अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट किसी भी कृषि उपज को उसमें जोड़ सकती है या उसमें से उसे हटा सकती है और इस पर उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना इसके जारी करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा पटल पर रखी जाएगी।

अध्याय-7

शास्ति

72. कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या किसी नियम या उप-विधियों अथवा तदधीन जारी आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन समनुदेशित कर्तव्यों का अनुपालन करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर, साधारण कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

अधिनियम,
नियमों और
उप-विधियों
के उल्लंघन
के लिए
शास्ति।

परन्तु यह कि जारी रहने वाले उल्लंघन की दशा में वह अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन पहली दोषसिद्धि के पश्चात् जारी रहता है, पच्चास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

73. जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट किसी भी जुर्माने के अतिरिक्त, जो अधिरोपित किया जा सकेगा, इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन फीस की रकम या उससे देय किसी अन्य रकम को संक्षेपतः वसूल करेगा और, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को संदत्त करेगा और अभियोजन की लागत को वसूल कर सकेगा और, यथास्थिति, बोर्ड या समिति को संदत्त कर सकेगा।

मण्डी देयों
की वसूली।

74. बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा या समिति के सचिव द्वारा या इस निमित्त बोर्ड या समिति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद (शिकायत) के सिवाय प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

अपराधों का
संज्ञान।

अपराधों का
शमन करने
की शक्ति।

75. (1) समिति किसी भी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम (इस अधिनियम की धारा 27 के उल्लंघन से अन्य) या नियमों या उप-विधियों के अधीन अपराध किया है या इसके किए जाने का उस पर युक्तियुक्त संदेह है तो समिति ऐसे अपराध का शमन कर के,—

(क) जहाँ अपराध, किसी फीस या इस अधिनियम के अधीन या तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के अधीन वसूलीय अन्य रकम के संदाय में असफलता या अपवर्चन से बनता है तो इस प्रकार वसूलीय फीस या अन्य रकम के अतिरिक्त, फीस की रकम से अन्यून धन राशि या फीस की रकम या अन्य रकम के पांच गुणा से अनधिक अन्य रकम स्वीकार कर सकेगी; और

(ख) अन्य मामलों में पांच हजार रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी भी अपराध के शमन पर, ऐसे किसी अपराध की बाबत सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी या जारी नहीं रहेगी, और यदि किसी न्यायालय में उस अपराध की बाबत, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही पहले से संस्थित की गई है तो शमन से उस की दोषमुक्ति हो जाएगी।

अध्याय-8

प्रकीर्ण

संविदा करने
का ढंग।

76. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, स्थावर सम्पत्ति का क्रय करने, विक्रय करने, पट्टा करने, बंधक करने, अन्तरण करने या हित का अर्जन करने के लिए, समिति के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, समिति की ओर से कोई भी संविदा या करार निष्पादित नहीं किया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय—

(क) समिति का सचिव, समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा जहाँ ऐसी संविदा या

करार की रकम या मूल्य, उन विषयों के बारे में जिन की बाबत वह समिति के संकल्प द्वारा सामान्यतः या विशेषतया ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ख) समिति का अध्यक्ष और सचिव, समिति की ओर से, संयुक्त रूप से संविदा या करार कर सकेगा जब ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक नहीं है;

(ग) खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट से अन्य किसी मामले में, समिति की ओर से संविदा या करार, अध्यक्ष, सचिव और समिति के दो अन्य सदस्यों, जिन में से एक पदेन सदस्य होगा जिसे समिति के संकल्प द्वारा ऐसा करने को सामान्यतः या विशेषतः प्राधिकृत किया गया है, द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा।

(3) समिति द्वारा की गई प्रत्येक संविदा, लिखित में होगी और उप-धारा (2) के अधीन ऐसा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, समिति की ओर से, हस्ताक्षरित की जाएगी।

(4) उप-धारा (1), (2) या (3) के उपबन्धों के अधीन निष्पादित संविदा से अन्य कोई भी संविदा, समिति पर आबद्धकार नहीं होगी।

(5) जहां कोई संविदा या करार समिति की ओर से किया जाता है, वहां समिति का सचिव, ऐसी संविदा या करार करने की तारीख के पश्चात् की गई इसकी आगामी बैठक में, तथ्य की समिति को रिपोर्ट करेगा।

1994 का 13.

1994 का 12.

77. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 और हिमाचल

प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचित मण्डी क्षेत्र, जो अधिसूचना में विहित किया जा सकेगा, के भीतर लाई गई या अमिप्राप्त की गई धारा 19 के अधीन अधिसूचित ऐसी कृषि उपज

कतिपय कृषि
उपज पर
बुगी संदेय
नहीं।

पर, किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, नगरपालिका समिति या नगर निगम को, ऐसी तारीख, जैसी इसमें विनिर्दिष्ट की जाए, से कोई चुंगी देय नहीं होगी।

बोर्ड और
समिति के
लिए भूमि का
अर्जन।

78. (1) जब कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है, तो राज्य सरकार, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अनुरोध पर, अपेक्षा करते हुए, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के उपबन्धों के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए अग्रसर होगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर और भूमि अर्जन के मददे राज्य सरकार द्वारा उपगत अन्य प्रमारों के, यथास्थिति, बोर्ड या समिति द्वारा संदाय पर, भूमि, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में निहित हो जाएगी। 1894 का 1.

(2) बोर्ड या समिति भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरण समझी जाएगी।

बोर्ड और
समिति का
अधिक्रमण।

79. (1) जब राज्य सरकार की यह राय है कि बोर्ड अपने कृत्यों का अनुपालन करने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहा है या इसने इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रम या दुरुपयोग किया है तो यह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा बोर्ड का अधिक्रमण कर सकेगी :

परन्तु यह कि अधिक्रमण का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार ने बोर्ड को इसके विरुद्ध अभिकथनों की बाबत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया है।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि समिति अपने कृत्यों का अनुपालन करने या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है या इसने इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन इसे प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रम या दुरुपयोग किया है तो यह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, समिति का अधिक्रमण कर सकेगी:

परन्तु यह कि अधिक्रमण का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार ने समिति को, इस के विरुद्ध

अभिकथनों की बाबत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का, युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया हो।

(3) उप-धारा (2) के अधीन समिति का अधिक्रमण करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों द्वारा पद धारण करना समाप्त हो जाएगा और राज्य सरकार, धारा 30 के अधीन नई समिति गठित करने के लिए पग उठाएगी और जब तक नई समिति का गठन नहीं कर दिया जाता बोर्ड, समिति के कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए छः मास से अनधिक अवधि के लिए ऐसे प्रबन्ध, जैसे वह उचित समझे, करेगा और उस प्रयोजन हेतु निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन समिति और इस के अध्यक्ष के सभी कृत्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का पालन, प्रयोग और निर्वहन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे बोर्ड इस निमित्त नियुक्त करे और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी, यथास्थिति, समिति या अध्यक्ष समझा जाएगा।

80. (1) यदि इस अधिनियम, तदधीन बनाए गए नियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अधीन किसी प्रायोजक और संविदा खेती उत्पादक के बीच या बोर्ड और व्यापारी के बीच अथवा समिति या व्यापारी के बीच किए गए किसी करार या संविदा के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे सुलह और माध्यस्थम् के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

विवाद की दशा में माध्यस्थम् को निर्देश।

(2) माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सुलह और माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होगा।

81. (1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की तारीख से ही हिमाचल प्रदेश कृषि उपज अधिनियम, 1969 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड उत्पादित हो जाएगा।

हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड का उत्सादन और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों का अन्तरण।

(2) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के उत्सादन की तारीख से ही—

(क) हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद धारण करना समाप्त हो जाएगा;

(ख) सभी संपत्तियाँ, निधियाँ और शोध्य रकमें (देय) जो हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड में निहित हैं या उसके द्वारा वसूली योग्य हैं बोर्ड में निहित हो जाएंगी और उसके द्वारा वसूली योग्य होंगी; और

(ग) ऐसी सभी देनदारियाँ जो हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, बोर्ड के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के उत्पादन से ठीक पूर्व की गई सभी संविदाएँ, करार और अन्य लिखित जिन में हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड पक्षकार है या जो हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के पक्ष में हैं हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा, के साथ या के लिए की गई समझी जाएंगी।

(4) सभी वाद, अपीलें या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ जो हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन के ठीक पूर्व संस्थित हैं या जो संस्थित की जा सकती थीं बोर्ड द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अन्तर्गत भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन कोई कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं।

(5) हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के सभी कर्मचारी, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन की तारीख से ही बोर्ड के कर्मचारी हो जाएंगे और बोर्ड में सेवा के उन्ही निबंधनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे और इस रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनके सेवा निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं।

(6) उप-धारा (5) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, जहाँ हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के किसी भी कर्मचारी ने उप-धारा (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के उत्पादन की तारीख से ठीक बाद के तीन मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय बोर्ड को,

बोर्ड का कर्मचारी न रहने के अपने आशय की लिखित में नोटिस द्वारा सूचना दी हो तो वह, बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे उपदान, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी उसे नियमों या हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अनुमोदन (आथोराईजेशन) के अधीन इसके उत्सादन से ठीक पूर्व, साधारणतः अनुज्ञेय हैं।

(7) यदि कोई ऐसा विवाद या ऐसी शंका उद्भूत होती है कि इस धारा के अधीन हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की कौन सी सम्पत्तियां, अधिकार, देनदारियां बोर्ड को अंतरित की गई हैं या हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, किन्हें, बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में माना जाना है, तो ऐसे विवाद या शंका को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

82. (1) इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन कृषि उपज मण्डी समितियों की स्थापना की तारीख से ही हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1969 के अधीन स्थापित मण्डी समितियां उत्सादित हो जाएंगी।

मण्डी
समितियों का
उत्सादन और
इनकी
परिसंपत्तियों
और
देनदारियों
का अन्तरण।

(2) उप-धारा (1) के अधीन मण्डी समितियों के उत्सादन की तारीख से ही—

(क) मण्डी समितियों के अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद धारण करना समाप्त हो जाएगा;

(ख) सभी संपत्तियां, निधियां और शोध्य रकमें (देय) जो मण्डी समितियों में निहित हैं या उनके द्वारा वसूली योग्य हैं कृषि उपज मण्डी समितियों में निहित हो जाएंगी और उनके द्वारा वसूली योग्य होंगी; और

(ग) ऐसी सभी देनदारियां जो मण्डी समितियों के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, कृषि उपज मण्डी समितियों के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन मण्डी समितियों के उत्पादन से ठीक पूर्व की गई सभी संविदाएं, करार, और अन्य लिखित जिन में ऐसी मण्डी समितियां पक्षकार हैं या जो ऐसी मण्डी समितियों के पक्ष में हैं क्रमिक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा, के साथ या के लिए की गई समझी जाएंगी।

(4) सभी वाद, अपीलें या विधिक कार्यवाहियां जो मण्डी समितियों द्वारा या उनके विरुद्ध उप-धारा (1) के अधीन इनके उत्पादन से ठीक पूर्व संस्थित हैं या जो संस्थित की जा सकती थीं क्रमिक कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा या के विरुद्ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए विधिक कार्यवाहियों के अंतर्गत भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कोई कार्यवाही सम्मिलित है।

(5) मण्डी समितियों के सभी कर्मचारी, उप-धारा (1) के अधीन इसके उत्पादन की तारीख से ही कृषि उपज मण्डी समितियों के कर्मचारी हो जाएंगे और ऐसी मण्डी समितियों में सेवा के उन्ही निबंधनों और शर्तों पर पद धारित करेंगे और इस रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनके सेवा निबन्धन और शर्तें, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, बोर्ड द्वारा परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं।

(6) उप-धारा (5) में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां मण्डी समितियों के किसी भी कर्मचारी ने उप-धारा (1) के अधीन मण्डी समितियों के उत्पादन की तारीख से ठीक बाद के तीन मास के अवसान से पूर्व किसी भी समय बोर्ड को, कृषि उपज मण्डी समितियों का कर्मचारी न बनने के अपने आशय की लिखित में नोटिस द्वारा सूचना दी हो तो, वह कृषि उपज मण्डी समितियों का कर्मचारी नहीं रहेगा और ऐसे उपदान, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जैसी उसे नियमों या हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के अनुमोदन (आथोराइजेशन) के अधीन इनके उत्पादन से ठीक पूर्व साधारणतः अनुज्ञेय हैं।

(7) यदि कोई विवाद या शंका उद्भूत होती है कि इस धारा के अधीन मण्डी समितियों की कौन सी संपत्तियां, अधिकार, देनदारियां कृषि उपज मण्डी समितियों को अन्तर्गत की गई हैं या मण्डी समितियों के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से, किन्हें, कृषि उपज मण्डी समितियों के कर्मचारियों के रूप में माना जाना है, तो ऐसे विवाद या शंका को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

83. (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा,—

- (क) धारा 2 (यठ) के अधीन फुटकर विक्रय के लिए कृषि उपज की मात्रा;
- (ख) धारा 10 के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को बोर्ड की निधि में से संदत्त की जाने वाली आसीन फीस और मत्ते;
- (ग) धारा 11 की उप-धारा (2) (V) के अधीन बोर्ड के लेखों का अनुरक्षण करने और उनकी लेखा परीक्षा के लिए प्रक्रिया और रीति;
- (घ) धारा 11 की उप-धारा (2) (Xii) के अधीन कृषि उपज के श्रेणीकरण, मानकीकरण और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के उन्नयन (संवर्धन) के लिए, कृषि उपज विपणन मानक ब्यूरो द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य और कृत्य;
- (ङ) प्रशासन, लेखों और अभिलेखों तथा कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के निपटान के मामले में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद पर पर्यवेक्षण करने और नियंत्रण रखने में प्रबन्ध निदेशक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (च) धारा 12 (iii) के अधीन बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रयुक्त और निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कर्तव्य;

- (छ) धारा 12 (viii) के अधीन बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेखों का अनुरक्षण करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ज) उपभोक्ता या किसान मण्डियों की स्थापना के लिए अवसंरचना का विकास और धारा 23 (1) के अधीन मण्डी क्षेत्र में उपभोक्ता को उत्पादक द्वारा सीधे कृषि उपज के विक्रय के लिए प्रक्रिया का विकास;
- (झ) संविदा खेती के लिए करार का प्ररूप और रीति जिसमें धारा 24 के अधीन कोई व्यक्ति संविदा खेती उत्पादक के साथ करार करेगा;
- (ञ) प्राइवेट प्रांगण, उपभोक्ता और किसान मण्डी की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने के लिए आवेदन, अवधि जिस के लिए अनुज्ञप्ति दी जानी है, अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्तें और धारा 25 (1) के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (ट) धारा 26 (ड) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दकरण के लिए निर्हताएं;
- (ठ) कृषि उपज की अधिकतम मात्रा, जो उत्पादक द्वारा घरेलू उपभोग के लिए किसी व्यक्ति को सीधे विक्रीत की जा सकती है और कृषि उपज के क्रय या विक्रय की अधिकतम मात्रा जो धारा 27 की उप-धारा (2) के अधीन छोटे व्यापारी द्वारा ली जा सकती है;
- (ड) धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन मार्केट प्रांगण में अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय के लिए कीमत के परिनिर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली पारदर्शी पद्धति;
- (ढ) धारा 34 की उप-धारा (3) के अधीन अपने कारबार के संचालन के लिए समिति द्वारा अपनाई जाने वाली रीति और प्रक्रिया;
- (ण) समिति द्वारा विक्रयों, तोल, परिदान, संदाय के करारों को कार्यान्वित और प्रवर्तित या रद्द करने और धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (iv) के अधीन अधिसूचित कृषि उपज की मण्डी से संबंधित सभी अन्य विषयों के विनियमन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

- (त) धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (xvi) के अधीन मण्डी कृत्यकारियों द्वारा लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण करने के लिए अपनाया जाने वाला प्ररूप और रीति तथा प्रक्रिया;
- (थ) धारा 39 की उप-धारा (3) के खण्ड (iv) के अधीन विक्रय के लिए मण्डी क्षेत्र में मानक दर के अनुसार (स्टैंडर्ड वाइज) लाई गई कृषि उपज की पहुंच के डाटे और दरों का अनुरक्षण करने और परिचालन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और रीति;
- (द) रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण का प्ररूप, अवधि जिसके भीतर रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण नवीकरण के लिए आवेदन दिया जाना है और धारा 40 (1) और (3) के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की फीस;
- (ध) धारा 44 के अधीन मण्डी फीस के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए समिति द्वारा अपनाई जाने वाली रीति और प्रक्रिया;
- (न) निबंधन और शर्तें जिन के अध्यक्षीन धारा 46 की उप-धारा (4) के खण्ड (v) के अधीन विपणन विकास निधि से ऋण और अनुदान प्रदान करके, वित्तीय रूप से कमजोर समितियों की सहायता की जा सकेगी;
- (प) धारा 48 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में अपनाया जाने वाला प्ररूप, समय और प्रक्रिया;
- (फ) रीति, जिस में समिति का शेष अधिशेष धारा 49 की उप-धारा (1) के अधीन विनिहित किया जाएगा;
- (ब) रीति, जिसमें माध्यस्थम् फीस के रूप में, समिति द्वारा अभिप्राप्त किया कोई धन, माध्यस्थम् कार्यवाही में लागत के लिए प्रतिभूति, प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के लिए अंशदान, अधिसूचित किसी कृषि उपज के बारे में संदाय, समिति द्वारा संदेय अन्य प्रभार या नियमों या उप-विधियों के अधीन समिति द्वारा अभिप्राप्त कोई धन, धारा 49 की उप-धारा (2) के अधीन रखा जाएगा;

- (म) प्ररूप, प्रक्रिया और रीति और अवधि जिस में, समिति, आगामी वर्ष के लिए धारा 50 की उप-धारा (1) के अधीन अपनी आय और व्यय का बजट तैयार और पारित करेगी;
- (म) समिति के अध्यक्ष और अन्य गैर-सरकारी सदस्यों तथा धारा 51 के खण्ड (ख) के अधीन समिति के कर्मचारियों को मानदेय और अन्य यात्रा भत्ता का संदाय करने के लिए रीति और प्रक्रिया;
- (य) शर्तें जिनके अधीन समिति मण्डी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि, भवन और उपस्कर पर प्रारम्भिक खर्च को पूरा करने के प्रयोजन के लिए धारा 52 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार या बोर्ड या अन्य समितियों या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकेगी;
- (यक) प्ररूप और रीति जिसमें संव्यवहार की विवरणी, धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए, समिति के सचिव को प्रस्तुत की जाएगी;
- (यख) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 68 की उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी; और
- (यग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब यह सत्र में हो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे जो एक सत्र में या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति, प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे। तथापि ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

84. (1) धारा 83 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, बोर्ड अधिसूचित मण्डी क्षेत्र की बाबत निम्नलिखित के लिए उप-विधियां बना सकेगा,—

उप-विधियां बनाने की शक्ति।

- (i) मण्डी समिति के कारबार के विनियमन के लिए;
- (ii) मण्डी में व्यापार की शर्तों के लिए;
- (iii) उप-समिति, यदि कोई हो, की शक्तियों, कर्तव्यों और कृत्यों के प्रत्यायोजन के लिए;
- (iv) इ-ट्रेडिंग को सामर्थ्यकारी और विनियमित करने के लिए; और
- (v) कोई अन्य विषय जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन उप-विधियां बनाई जानी हैं या मण्डी क्षेत्र में, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उप-विधियां विरचित करना आवश्यक हो।

(2) कोई भी उप-विधि तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि उन्हें सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित और अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है।

85. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, बोर्ड राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए विनियम विरचित कर सकेगा—

विनियम बनाने की शक्ति।

- (क) बोर्ड की बैठकें बुलाना और करना, समय और तारीख जब ऐसी बैठकें करनी होंगी, ऐसी बैठकों में कारबार का संचालन;
- (ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
- (ग) बोर्ड और मण्डी समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;
- (घ) बोर्ड की सम्पत्ति का प्रबन्धन;
- (ङ) बोर्ड की ओर से संविदाओं का निष्पादन;

- (च) लेखों का अनुरक्षण और बोर्ड द्वारा तुलनपत्र तैयार करना;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए प्रक्रिया;
- (ज) कोई अन्य विषय जिनके लिए विनियमों में उपबन्ध किया जाना है या किया जा सकेगा।

निरसन और
व्याप्तियां।

86. हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1969 को 1970 का 9. एतद्वारा निरसित किया जाता है:

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

- (क) निरसित अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन या तदधीन सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात, या
- (ख) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या
- (ग) निरसित अधिनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या
- (घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और कोई ऐसी शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानो यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं किया गया हो:

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन रहते हुए निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत की गई कोई नियुक्ति या किया गया प्रत्यायोजन, जारी की गई अधिसूचना, नोटिस, आदेश, अनुदेश या निदेश, विरचित नियम, विनियम, उप-विधियां, प्ररूप या स्कीम, प्राप्त प्रमाणपत्र, प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति, किया गया रजिस्ट्रीकरण, उद्गृहीत फीस है), जहां तक यह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं और इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएंगी और तदनुसार प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दी जाती।

अनुसूची
[धारा 2 (क) और धारा 71 देखें]

	अंग्रेजी नाम 2	हिन्दी नाम 3
1. अनाज	1. पैडी 2. राईस 3. व्हीट 4. गेज 5. बारले 6. बकव्हीट	घान चावल कनक मक्की जौ कूटद्
2. दालें	1. पिजियन पी 2. लैंटिल 3. बलैक ग्राम 4. ग्रीन ग्राम 5. पीज ड्राई 6. कॉउ पीज 7. पलसिज स्प्लिट 8. ग्राम 9. फ्रंचबीन/सोयाबीन	अरहर मसूर उड़द मूंग मटर खुश्क लोभिया दालें दली चना राजमाह/भराह
3. तिलहन	1. मसटर्ड 2. इंडियन रेप 3. लिनसीड 4. ग्राउंडनट शेल्ड एण्ड अनशेल्ड 5. सेसामम	सरसों तोरिया अलसी मूंगफली तिल
4. फल	1. मँगो 2. बँनाना 3. लीचीज 4. स्वीट औरेंज 5. लैमन 6. ग्रेपस 7. पोमेग्रेनेट-सीड 8. ऐपल 9. औरेंज 10. पीच	आम केला लीची मालटा नीम्बू अंगूर अनारदाना सेब संगतरा आड़ू

1	2	3
	11. प्लम	अलूचा
	12. पीयरज	नाशपाती
	13. गौवा	अमरुद
	14. चिलगोजा	नियोजा
	15. एपरीकाट	खुरमानी
	16. परसीमॉम	जपानी फल
	17. वाटर मेलन	तरबूज
	18. वालनट	अखरोट
	19. आलमन्ड	बादाम
	20. मस्कमेलन	खरबूजा
	21. पपाया	पपिता
5. सब्जियां	1. पोटेटोज	1. आलू
	2. आनियन ड्राई	प्याज खुष्क
	3. ब्रिंजल	बैंगन
	4. वोटल गॉर्ड	धिया
	5. लेडी फिंगर्ज	भींडी
	6. रेड गौर्ड	हलवा कद्दू
	7. टोमैटो	टमाटर
	8. कोलीफलावर	फुलगोभी
	9. कैबेज	बंदगोभी
	10. स्प्रॉज गौर्ड	धिया तोरी
	11. ग्रीन पीज	मटर हरी
	12. फेन्चवीन	फासबीन
	13. लीब्ज ऑफ इण्डियन कोल्जा मस्टर्ड एण्ड स्पैनिश ऐटस्ट्रू	साग
	14. कौरट	गाजर
	15. रेडिश	मूली
	16. टरनिप	शलगम
	17. टिंडा गौर्ड	टींडा
	18. —	कटहल
	19. —	जिभीकन्द
	20. अरम	अरबी
	21. —	कचालू
	22. फेनूग्रीक	मेथी हरी
	23. हिलकैपसीकम	मिर्च बड़ी
	24. बिटर गौर्ड	करेला
	25. ऐश गौर्ड	पेठा
	26. कुकम्बर	खीरा

1	2	3
6. रेशा	1. काटन जिण्ड एण्ड अनजिण्ड	कपास और रूई
7. पशु पालन उत्पाद	1. पोलटरी 2. ऐगज 3. कैटल 4. शीप 5. गोट 6. वूल 7. बटर 8. घी 9. मिल्क 10. गोट मीट एण्ड मटन 11. फिश	— अण्डा — भेड़ बकरी ऊन मक्खन घी दूध बकरी और भेड़ का गोश्त मछली
8. वासक मसाले और अन्य	1. जिंजर 2. गारलिक ड्राई 3. चीलीज ड्राई एण्ड ग्रीन 4. टरमेरिक 5. कोरीएंडर	अदरक लहसुन खुष्क मिर्च हल्दी धनिया खुष्क और हरा
9. स्वापक पदार्थ	1. टोवेको	तम्बाकू
10. विविध	1. शूगरकेन 2. गुड़ एण्ड शक्कर 3. — 4. बार्क आफ वालनट 5. — 6. एडिबल मशरूम 7. — 8. भावर घास 9. डिस्कोरिया 10. कमरु पट्टी पट्टीज 11. केच्यू 12. वाइऊला 13. सौसरीअलापा 14. टिम्बर	गन्ना गुड़ और शक्कर खांडसारी दंदासा धूप गूच्छी बनकसा भावर घास सिंगली-भिंगली पतियां कथा आम्बला कूठ इमारती लकड़ी

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कृषि वस्तुओं में व्यापार के उदारीकरण के फलस्वरूप कृषि विपणन, विश्व भर में, प्रमुख परिवर्तनों का दृष्टसाक्षी है। कृषक समुदाय को, नई मण्डी अभिगमन अवसरों से, स्वदेश के साथ-साथ विश्व स्तर पर, अधिकतम उपयोगिता (बाजार भाव) प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने हेतु देश की आन्तरिक विपणन प्रणाली को आधुनिकीकृत, एकीकृत तथा सशक्त करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की, जिसने देश में कृषि विपणन प्रणाली के साथ-साथ कृषि विपणन को विकसित करने और सशक्त करने की पालिसियों और प्रोग्रामों में विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया। रिपोर्टों से यह निरूपित हुआ है कि राज्य का कृषि मण्डियों पर नियन्त्रण सोकर्य बना दिया जाना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी को, विशिष्टतया विपणन अवसंरचना और सहायी सेवाओं के विकास के लिए अपेक्षित विशाल विनिधान के सृजन के लिए, सुकर बनाया जा सके। इन रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में चर्चा की गई। इन सम्मेलनों में राज्य सरकार ने यह मत दिया है कि कृषि विपणन क्षेत्र में सुधार, नियन्त्रणों की प्रणाली (प्रवृत्ति) से अलग होकर, एकल व्यवस्था (नियमन) और स्पर्धा के लिए, आवश्यक हैं। वैकल्पिक विपणन संरचना का उन्नयन (संवर्धन) करते समय राज्य सरकार को कृषकों/उत्पादकों को प्राइवेट व्यापारियों और उद्योगों द्वारा शोषण से बचाने के लिए, पर्याप्त रक्षोपाय करने की भी आवश्यकता है। इस लिए कृषि विपणन पर नया विधान लाने की आवश्यकता रही है। भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को "ड्राफ्ट लेजिस्लेशन माडल" भेजा है ताकि वे विषय पर अपने राज्य के लिए "माडल लेजिस्लेशन" से संगत, अधिनियम बना सकें।

विद्यमान हिमाचल प्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1969 के उपबन्ध इन विवाधकों के समावेदन के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस लिए समुचित विधान के अधीन नए संस्थानों को स्थापित करना अनिवार्य समझा गया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड और कृषि उत्पाद मण्डी समितियों की स्थापना के लिए विधि को पुनः अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है।

प्रस्तावित विधान, राज्य में सीधी बिक्री तथा कृषि मण्डियों के प्रबन्धन और विकास में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के उन्नयन (संवर्धन) के लिए प्राइवेट मण्डियों और प्रांगणों, उपभोक्ता/कृषक मण्डियों की स्थापना का उपबन्ध करता है। यह राज्य में संविदा-खेती के विनियमन और उन्नयन (संवर्धन) के लिए, उत्पादकों के साथ कृषि उपज के किसी संव्यवहार में कमीशन अभिकरण को प्रतिषिद्ध करने, तथा फार्म स्तर पर किसानों और कृषकों द्वारा अपने वास्तविक उपयोग के लिए पशु-सलवन प्रबन्धन (पोस्ट हारविस्ट मेनिजमेन्ट) प्रसुविधाओं, जिसके लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार विभिन्न स्कीमों का उपबन्ध कर सकेगी, का सृजन करने के लिए भी उपबन्ध करता है।

राज कृष्ण ग.
प्रभारी मन्त्र

शिमला :

तारीख,....., 2005.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं इस लिए राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विधेयक का खण्ड 83 राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है और खण्ड 84 और 85 बोर्ड को क्रमशः उप-विधियां और विनियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य प्रवृत्ति का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन)

विधेयक, 2005

विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में, कृषि उपज के विपणन, दक्षतापूर्ण विपणन प्रणाली के विकास, कृषि सम्बन्धी प्रसंस्करण और कृषि निर्यात, स्थापन के उन्नयन और कृषि उपज के लिए मण्डियों के उचित प्रशासन हेतु समुन्नत विनियमन का उपबन्ध करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य में और से कृषि उपज के विपणन के लिए सुप्रशासित और दक्षतापूर्ण अवसंरचना की अभिवृद्धि करने हेतु, प्रसुविधाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए न्यूनतम मानकों के व्यवस्थापन के माध्यम से परिचालन द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक मण्डियों के लिए सन्तुलित व्यापार क्षेत्र (लैवल प्लेइंग फील्ड) सुनिश्चित करने हेतु विधि को पुनः अधिनियमित करने के लिए विधेयक।

राज कृष्ण गौड,
प्रभारी मन्त्री।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि)।

शिमला:

तारीख..... 2005.

Bill No. 11 of 2005

**THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION)
BILL, 2005**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for improved regulation in marketing of agricultural produce, development of efficient marketing system, promotion of agri-processing and agricultural exports, establishment and proper administration of markets for agricultural produce in the State of Himachal Pradesh and to ensure level playing field for competitive markets to operate through setting of minimum standards for facilities, procedures and systems, thereby promoting the establishment of well administered and efficient infrastructure for marketing of agricultural produce in and from the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows: —

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Agricultural and Horticultural Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005. Short title.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,— Definitions.

(a) “agricultural produce” means all produce and commodities, whether processed or unprocessed of agriculture, horticulture, apiculture, sericulture, livestock and products of livestock, fleeces (raw wool) and skins of animals, forest produce and fisheries as are specified in the Schedule to this Act or declared by the Government by notification under section 19 of this Act and also includes a mixture of two or more than two such products;

(b) “agriculturist” means a person who is a *bonafide* Himachali and owns and possesses land in Himachal Pradesh and who is engaged in production of agricultural produce by himself or by hired labour or otherwise, but does not include any market functionary;

(c) “Board” means the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board established under section 3 of this Act;

- (d) "business" means purchase, sale, processing, value addition, storage, transportation and connected activities of agricultural produce;
- (e) "buyer" means a person, a firm, a company or a Cooperative Society or Government Agency, Public Undertaking/ Public Agency or Corporation, commission agent, who himself or on behalf of any other person or agent buys or agrees to buy agricultural produce in the notified market area;
- (f) "bye-laws" means the bye-laws made by the Board for the Committee under section 84 of this Act;
- (g) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (h) "commission agent" means a person who on behalf of his principal trader and in consideration of a commission or percentage on the amount involved in such transaction buys agricultural produce and makes payment, keeps it in his custody and delivers it to the principal trader in due course or who receives and takes in his custody agricultural produce sent for sale within the market area or from outside the market area, sells the same in the market area and collects payment thereof from the buyer and remits the sale proceeds to his principal trader;
- (i) "Committee" means an Agricultural Produce Market Committee established under section 29;
- (j) "contract farming" means farming by a person called "Contract Farming Producer" under a written agreement with another person called "Contract Farming Sponsor" to the effect that his farm produce shall be purchased as specified in the agreement;
- Explanation.*— "Contract Farming Producer" means an individual agriculturist or an association of agriculturists by whatever name called registered under any law for the time being in force;
- (k) "Contract Farming Agreement" means the agreement made for a specific period for contract farming between Contract Farming Sponsor and Contract Farming Producer;
- Explanation.*— "contract farming sponsor" means a sole proprietor, a company registered under the Companies Act, 1956, a partnership firm registered under the Partnership Act, 1932, a Government Agency, the Cooperative Societies registered under the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968, and shall include its administrators, successors, representatives and assignees;
- (l) "Cooperative Society" means a Cooperative Society of producers registered under the provisions of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968, which deals in the purchase, sale, processing, or storage of agricultural produce, or is otherwise engaged in the business

of disposal of agricultural produce;

- (m) "export" means despatch of agricultural produce outside India;
- (n) "exporter" means a person who exports agricultural produce;
- (o) "e- trading" means trading in which billing, booking, contracting, negotiating, information exchange, record keeping and other connected activities are done electronically on computer network/ internet;
- (p) "hamal" means a labourer, hamal or coolie engaged for dara-making, loading, unloading, filling, stitching, emptying or carrying any agricultural produce in the notified market area;
- (q) "import" means bringing agricultural produce from outside India;
- (r) "importer" means a person who imports agricultural produce from outside India;
- (s) "licence" means licence granted under this Act;
- (t) "licensee" means a person or an association, firm, company, public sector undertaking or society holding a licence issued under this Act;
- (u) "market" means a market established under section 19 of this Act which includes market area, market yard/ sub yards and principal market yard;
- (v) "market area" means area notified under section 19 of this Act;
- (w) "market charges" includes charges on account of or in respect of commission, brokerage, weighing, measuring, hammaling (loading, unloading or carrying), cleaning, drying, sieving, stitching, stacking, hiring, gunny bags, stamping, bagging, storing, warehousing, grading, surveying, transporting and processing;
- (x) "market functionary" means a trader, a commission agent, buyer, hamal, processor, stockist and any other person as may be declared by the State Government, by notification, to be a market functionary;
- (y) "market yard" in relation to a market area means a specified place and includes any enclosures, buildings or locality declared as such in any market area by the State Government by notification;
- (z) 'member' includes the Chairman of the Board;
- (za) "marketing" means all activities involved in the flow of agricultural produce from the production points commencing from the stage of harvest till these reach the ultimate consumers viz, grading, processing, storage, transport, channels of distribution and all other functions involved in the process;

- (zb) "notification" means notification issued under this Act and published in the Official Gazette;
- (zc) "notified agricultural produce" means any agricultural produce notified under section 19 of this Act;
- (zd) "person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;
- (ze) "producer" means a person, who in his normal course of avocation, grows, manufactures, rears or produces, as the case may be, agricultural produce personally, through tenants or otherwise, but does not include a person who works as a trader or a broker or who is a partner of a firm of traders or brokers is otherwise engaged in the business of disposal or storage of agricultural produce other than that grown, manufactured, reared or produced by himself through his tenants or otherwise;

Provided that no person shall be disqualified from being a producer merely on the ground that he is a member of a Cooperative Society;

Explanation,— The term "producer" shall also include tenant'.

- (zf) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (zg) "processing" means any one or more of a series of treatments relating to powdering, crushing, decorticating, dehusking, parboiling, polishing, ginning, pressing, curing, cleaning, or any other manual, mechanical, chemical or physical treatments to which raw agricultural produce or its product is subjected to;
- (zh) "processor" means a person who undertakes processing of any notified agricultural produce on his own accord or on payment of a charge;
- (zi) "private market yard" means such place other than the market yard/sub market yard in the market area where infrastructure has been developed and managed by a person for marketing of the notified agricultural produce holding a licence for this purpose under this Act;
- (zj) "registration" means registration done under this Act;
- (zk) "regulation" means regulations made by the Board under section 85 of this Act;
- (zl) "retail sale" means sale of agricultural produce not exceeding such quantity as may be prescribed;
- (zm) "State Government" or "Government" means the Government of Himachal Pradesh;

- (zn) "seller" means a person who sells or agrees to sell any agricultural produce;
- (zo) "trader" means a person who in his normal course of business buys or sells any notified agricultural produce and includes a person engaged in processing of agricultural produce but does not include an agriculturist;
- (zp) "transportation" means taking agricultural produce by push cart, bullock cart, truck or other vehicle in course of business for marketing from one place to another;
- (zq) "transporter" means a person who transports agricultural produce; and
- (zr) "value addition" means processing, grading, packing or other activities due to which value is added to agricultural produce.

CHAPTER-II

ESTABLISHMENT, CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE BOARD

3. (1) The State Government may, by Notification, for coordinating the activities of markets and for development, promotion and regulation of agricultural marketing, establish the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board. Establishment of the Board.

(2) The Board shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall be competent to acquire and hold property both movable and immovable and to lease, sale or otherwise transfer any such property and to contract and to do all other things necessary for the purpose for which it is established.

4. The Board shall consist of a Chairman, who shall be appointed by the State Government and twenty members including Vice-Chairman of whom ten shall be *ex-officio* members and ten non-official members to be nominated by the State Government in the following manner, namely:— Constitution of the Board.

(a) *Ex-officio members:*

- (i) The Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh .. Vice-Chairman;
- (ii) The Secretary (Horticulture) to the Government of Himachal Pradesh;
- (iii) The Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh;
- (iv) The Secretary (Forest) to the Government of Himachal Pradesh;
- (v) The Principal Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh;
- (vi) Director of Agriculture, Himachal Pradesh;
- (vii) Director of Horticulture, Himachal Pradesh;
- (viii) Registrar, the Cooperative Societies, Himachal Pradesh;
- (ix) Chief General Manager of National Bank for Agriculture and

Rural Development, Shimla; and

(x) Managing Director of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.

(b) *Non – official members :*

- (i) two shall be chairmen of the Committees;
- (ii) four shall be other progressive agriculturists/farmers;
- (iii) two shall be from amongst such traders registered under section 40 of this Act; and
- (iv) two shall be from amongst experts having experience in agricultural marketing.

Term of office of the Chairman and non-official members of the Board.

5. (1) The Chairman and the non-official members of the Board shall hold office during the pleasure of the State Government. In the event of supersession of the committee from where the members have been nominated in the Board, the concerned member shall cease to be a member of the Board.

(2) The tenure of the Vice-Chairman and *ex-officio* members of the Board shall come to an end as soon as he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

(3) Whenever there is a temporary vacancy in the office of the Chairman, the Vice- Chairman shall act as the Chairman during the vacancy.

Disqualification of members of the Board.

6. No person shall be eligible to become a member of the Board, who,—

- (a) does not ordinarily reside within Himachal Pradesh;
- (b) is below 25 years of age;
- (c) has been removed under section 8 or section 33 of this Act;
- (d) is of unsound mind; and
- (e) has been declared insolvent or sentenced by a criminal court, whether within or outside Himachal Pradesh for an offence involving moral turpitude:

Provided that the disqualification under clause (e) on the ground of a sentence by a criminal court shall not apply after the expiry of four years from the date on which the sentence of such person has expired.

Resignation of members of the Board.

7. The Chairman of the Board may resign by tendering his resignation to the State Government, and a member other than the Chairman of the Board may resign from membership by tendering his resignation to the State Government through the Chairman of the Board, and the seat of such Chairman or the member, as the case may be, shall become vacant on the date of acceptance of his resignation.

Removal of members of the Board.

8. The State Government may remove any non-official member of the Board who has become subject to any of the disqualifications specified in section 6 or who is, in its opinion, unfit to act, as a member or remiss in the discharge of his duties or whose continuance as a member of the Board is considered to be prejudicial to its interest and may appoint another member of the Board in his place in the manner as provided under section 4 from the category to which the removed member belongs :

Provided that before removing a member, the reasons for the proposed action shall be conveyed to him and his reply, invited within a specified period and duly considered:

Provided further that any vacancy of the non-official member shall be filled in as early as practicable.

9. (1) The Board shall have a Managing Director who shall be appointed by the State Government and he shall also be the Chief Executive Officer of the Board.

Appointment of officers and servants of the Board.

(2) The Managing Director appointed under sub section (1) shall also function as the Member Secretary of the Board.

(3) For the efficient discharge of duties and functions of the Board and the Committees, the Board may, with the prior approval of the State Government, appoint such other officers including civil Engineer and employees as may be necessary.

(4) The superintendence and control over all the officers and employees of the Board and the Committees shall vest in the Managing Director of the Board.

10. The Chairman and non-official members of the Board shall be paid from the Marketing Development Fund such sitting fees and allowances, as may be prescribed.

Allowances of the Chairman and non-official members of the Board.

11. (1) The Board shall, subject to the provisions of this Act, perform the following functions and shall have powers to do such things, as may be necessary or expedient for carrying out these functions:—

Powers and functions of the Board.

- (i) exercise superintendence and control over all the Committees established and constituted under this Act;
- (ii) coordinate the working of the Committees and other affairs thereof including programmes undertaken by such Committees for the development of markets and market areas;
- (iii) undertake the State level planning of the development of agricultural produce markets;
- (iv) administer the Marketing Development Fund;
- (v) to give directions to the Committees in general or any Committee in particular with a view to ensure improvement thereof;
- (vi) any other function specifically entrusted to it by this Act; and
- (vii) such other functions of like nature, as may be entrusted to the Board, by the State Government.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such functions of the Board shall include.—

- (i) to approve proposals for selection of new sites by the Committees for establishment of principal or sub-market yard;
- (ii) to approve proposal for constructing infrastructure facilities in the market area such as grading, pack houses, storages, processing, other post harvest management facilities etc;
- (iii) to supervise and guide the Committee in the preparation of plans and estimates of construction programme undertaken by the Committee;
- (iv) to execute all works chargeable to the Board's fund;
- (v) to maintain accounts and get the same audited in such form and in such manner as may be prescribed;
- (vi) to publish annually at the close of the year its progress report, balance sheet and statement of assets and liabilities and send copies thereof to each member of the Board and the State Government;
- (vii) to undertake marketing extension activities in the Board for the transfer of marketing technology and extension services. It may also make necessary arrangements for propaganda and publicity on matters related to regulated marketing of an agricultural produce and development of marketing;
- (viii) to provide facilities for the training of officers and staff of Committees and the Board after assessing the demand for trained personnel in agricultural marketing at all levels;
- (ix) to prepare and adopt budget for the ensuing year;
- (x) arrange or organize seminars/ workshops/ exhibitions etc. on subjects related to agricultural marketing;
- (xi) to do such other things as may be of general interest to the Committees or considered necessary for the efficient functioning of the Board;
- (xii) to organise and promote grading and standardization of notified agricultural produce and e-trading; and
- (xiii) to set up an Agricultural Produce Marketing Standards Bureau to perform such functions and duties as may be prescribed for the purpose of promotion of grading, standardization and quality certification of agricultural produce in the State.

Powers and functions of the Managing Director of the Board.

12. The Managing Director of the Board shall,—

- (i) exercise supervision and control over officers and staff of the Board in matters of executive administration, concerning accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees in accordance with the procedure as may be prescribed;
- (ii) incur expenditure from the Marketing Development Fund on the sanctioned items of work;
- (iii) have the same powers as are conferred under the financial rules of the State Government on the Head of the Department and

exercise such other powers and discharge such other duties as may be prescribed;

- (iv) have the power to transfer employees of one Committee to the Board and *vice-versa* on administrative grounds;
- (v) in case of emergency, direct the execution or stoppage of any work and doing of any act which requires the sanction of the Board;
- (vi) prepare annual budget of the Board;
- (vii) arrange for internal audit of the Board;
- (viii) arrange for the meeting of the Board and maintain records of the proceedings of the meetings of the Board in accordance with the procedure as may be prescribed;
- (ix) take such steps as deemed necessary for execution of the decision of the Board;
- (x) inspect the construction work undertaken by the Committees either from their own funds or loans or grants provided by the Board or any other agency and take corrective measures;
- (xi) report such acts either of the Committees or of the Board which are contrary to the provisions laid down under this Act or rules and bye-laws made thereunder to the State Government; and
- (xii) take such steps as deemed necessary for effective discharge of the functions of the Board.

13. (1) The Board shall meet for the transaction of its business at least once in every three months at such place and at such time as the Chairman may determine. Meeting of the Board.

(2) All the proceedings of the Board shall be authenticated by the Chairman and the Managing Director of the Board.

(3) The Board shall conduct the business in such manner as may be prescribed by regulations.

14. One third of the total members shall constitute a quorum at a meeting of the Board. All questions that may come up before a meeting of the Board shall be determined by a majority of votes of the members present and voting; and in case of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote. Quorum

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.

15. No act or proceedings of the Board shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy among its members or any defect in the constitution thereof. Act of the Board not to be invalidated.

16. The Board may appoint Sub-Committees consisting of three or more members which shall include the Chairman or the Vice-Chairman and the Managing Director of the Board, for the performance of any of its duties or functions or for giving Appointment of sub-Committees.

advice on any matter incidental thereto and may delegate to such Sub-Committee any of its duties or functions as it may deem necessary.

Superintendence and control of the Board.

17. The State Government shall exercise superintendence and control over the Board and its officers and may call for such information as it may deem necessary and, in the event of its being satisfied that the Board is not functioning properly, or is abusing its powers or is guilty of corruption or mis-management, it may suspend the Board and, till such time a new Board is constituted, make such arrangement for the exercise of the functions of the Board, as it may think fit:

Provided that the Board shall be constituted within six months from the date of its suspension.

Delegation of powers.

18. (1) The State Government may delegate to the Board any of powers conferred on it by or under this Act except power to make rules.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Board may by general or special order, delegate to the Managing Director of the Board or Sub-Committee appointed by it or to any officer of the Board, any of powers and duties conferred on it by or under this Act, as it may deem fit.

CHAPTER-III

REGULATION OF TRADING AND CONTRACT FARMING

Notification of intention of developing and regulating marketing of notified agricultural produce.

19. (1) The State Government on its own or on the representation made by the growers or on the recommendation of the Board may, by notification, declare its intention of exercising control over the purchase, storage, processing and sale of such agricultural produce, in such area as may be specified in the notification, by inviting objections or suggestions from the general public within a period of thirty days from the date of publication of notification which shall be considered by it.

(2) After the expiry of the period specified in the notification issued under sub-section (1), and after considering objections and suggestions, if any, received before the expiry of the specified period, and after making such inquiry, as may be necessary, the State Government may by notification, declare the area specified in the notification, or any portion thereof to be a market area for the purpose of this Act and that marketing of all or any of the kinds of agricultural produce specified in the notification shall be developed and regulated in such market area in accordance with the provisions of this Act.

Notification of intention to alter limits of or to split up market areas to de-establish a market.

20. (1) The State Government may, by notification, declare its intention —

- (a) to alter the limits of a market area by including within it any other area in the vicinity thereof or by excluding therefrom any area comprised therein; or
- (b) to amalgamate two or more market areas and constitute one Committee thereof; or

- (c) to split up a market area and to constitute two or more Committees thereof; or
- (d) to de-establish a market.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall define the limits of the area to be included in or excluded from a market area, or of the market area to be amalgamated into one, or of the area of each of the markets to be de-established, as the case may be, and shall also specify the period which shall not be less than six weeks from the date of publication of the notification within which objections or suggestions, if any, may be received by the State Government.

(3) Any person likely to be affected by the notification issued under sub-section (1) may, submit his objections or suggestions in writing to the State Government within the period specified in the notification.

(4) Objections and suggestions received under sub-section (3) within the stipulated period shall be considered and decided by the State Government and thereafter the State Government may, by notification,—

- (a) include the area or any part thereof in the market area or exclude it therefrom;
- (b) constitute a new Committee for the market area amalgamated; or
- (c) split up an existing market area and constitute two or more Committees for such areas, as the case may be; or
- (d) to de-establish a market.

(5) Where a notification under sub-section (4) has been issued excluding any area from the market area and including such area in other market area, the State Government shall, after consulting the Board and the Committee concerned frame a scheme to determine what portion of the assets and other properties vested in one Committee shall vest in the other Committee and in what manner the liabilities of the Committees shall be apportioned between the two Committees and such scheme shall come into force on the date of publication of the scheme in the Official Gazette.

21. (1) In every market area, there may be —

- (i) market yard managed by the Committee;
- (ii) one or more than one sub-market yards managed by the Committee; and
- (iii) private market yards, private markets farmers and consumer markets managed by a person other than a Committee.

Market yards,
sub-market
yards,
farmer's,
consumer's
and private
market yards.

(2) The Board may with the prior approval of the State Government, by notification, declare any specified place including any structure, enclosure, open place or locality in the market area to be a market yard or sub-market yards for the notified market area.

Establishment of private yards, and direct purchase of agricultural produce from agriculturists.

22. Any person who desires to establish private yard for the purchase of agricultural produce direct from agriculturists, or for providing infrastructure facilities in any market area for—

- (a) the process of the notified agricultural produce;
- (b) the trade of notified agricultural produce of particular specification;
- (c) the export of notified agricultural produce; and
- (d) the grading, packing and transaction in other way by value addition of notified agricultural produce,

shall make an application for obtaining the licence in accordance with the provisions of section 25 of this Act.

Establishment of consumer's or farmer's markets and creation of post harvest management facilities by the farmers/ agriculturists.

23. (1) Consumer's or farmer's market may be established by developing infrastructure as may be prescribed, by any person in any market area and producer may, himself sell his agricultural produce direct to the consumer in such market area, in the manner as may be prescribed.

(2) Market service charge shall be collected on sale of agricultural produce by the seller and shall be remitted to the proprietor of the consumer market.

(3) Save as otherwise provided in this Act, no market fee shall be leviable on the transactions undertaken in the consumer's or farmer's market.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any farmer and agriculturist may, for his bonafide use, create post harvest management infrastructure facilities at the farm level such as grading, standardization, pack houses, storages (including cold storages), primary processing of agricultural produce and other post harvest management facilities for which the central or the State Government may provide different scheme, which may be implemented alongwith the scheme under horticultural technology mission being executed by the Department of Horticulture through Directorate of Marketing and Inspection, the Government of India.

Contract farming.

24. No person shall undertake contract farming unless registered under section 40 of this Act, and shall have to enter into an agreement with contract farming producer on such form and in such manner as may be prescribed.

Grant and renewal of licence of private yard, consumer's and farmer's market.

25. (1) Any person who under section 22 desires to purchase notified agricultural produce direct from the agriculturists or the producer or wishes to establish a private market yard or under sub-section (1) of section 23 desires to establish consumer or farmer's market in one or more than one market area, shall apply to the Managing Director of the Board for grant or renewal of licence, as the case may be, for such period, in such form, on such conditions and on payment of such fees as may be prescribed.

(2) Application received under sub-section (1) for grant or renewal of licence may be accepted or rejected for the reasons to be recorded in writing provided that a

licence shall not be granted or renewed if,—

- (i) the Committee dues are outstanding against the applicant;
- (ii) the applicant is a minor or not bonafide;
- (iii) the applicant has been declared defaulter under the Act and the rules and bye-laws made thereunder;
- (iv) the applicant having been declared guilty in any criminal case and convicted by imprisonment;
- (v) the State Government is satisfied that granting or renewal of licence to the applicant is not going to promote the interest of the producers; and
- (vi) there is any other reason which the Managing Director of the Board may consider to be against the interest of the producer or the consumer.

26. Subject to the provisions of this Act, any licence issued or renewed under section 25, may be suspended or cancelled by the Managing Director of the Board, after affording the holder of such licence the opportunity of being heard, on any of the following grounds:—

Power to cancel or suspend licence.

- (a) if the licence has been obtained through willful mis-representation or fraud; or
- (b) if the holder of the licence or any of his servant or any person acting on his behalf, commits a breach of any of the terms or conditions of the licence; or
- (c) if the holder of the licence in combination with other licence holder commits any act or abstains from carrying on his normal business in the market area with the intention of wilfully obstructing, suspending or stopping the marketing of notified agricultural produce in the market yard/ submarket yard and in consequence whereof the marketing of any notified agricultural produce has been obstructed, suspended or stopped;
- (d) if the holder of the licence has become an insolvent; or
- (e) if the holder of the licence incurs any disqualification as may be prescribed; or
- (f) if the holder of the licence is convicted of any offence under this Act, then within one year of the conviction, if the conviction is for the first time, and within three years for subsequent conviction.

27. (1) No person shall, except in accordance with the provisions of this Act or rules or bye-laws made thereunder,—

Regulation of marketing of notified agricultural Produce.

- (i) use any place in the market area for the marketing of notified agricultural produce; and
- (ii) operate in the market area as a market functionary.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the following sale or purchase of such agricultural produce,—

- (i) where the sale is made by the producer himself to any person

for his domestic consumption in quantity upto the prescribed limit;

- (ii) purchase or sale of which is made by a petty trader as may be prescribed; and
- (iii) purchase of which is made by an authorized fair price shop dealer from the Food Corporation of India, the State Commodities Trading Corporation or any other agency or institution authorized by the State Government for distribution of the essential commodities through the Public Distribution System.

Sale of notified agricultural produce in the market.

28. (1) All notified agricultural produce shall ordinarily be sold in the market yards, sub-market yards or in the private yards of the licence holder, subject to the provision of sub-section (2):

Provided that notified agricultural produce may be sold at other places to a licence holder permitted in this behalf under section 22 and 23 of this Act:

Provided further that it may not be necessary to bring agricultural produce covered under contract farming to the market yard, sub market yard or private yard and such agricultural produce may be directly sold to contract farming sponsor from farmer's fields.

(2) The price of the notified agricultural produce, brought for sale into the market yard, shall be settled by open auction or by any other transparent system as may be prescribed and no deduction shall be made from the agreed price on any account whatsoever from the seller :

Provided that the price of the notified agricultural produce in the private yards shall be settled in the manner as may be prescribed.

(3) Weighment or measurement or counting of all the notified agricultural produce so purchased shall be done by such person and in such manner as may be provided in the bye-laws.

CHAPTER-IV

ESTABLISHMENT, CONSTITUTION, POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

Establishment of the Committee.

29. (1) The State Government shall, by notification, establish a Agricultural Produce Market Committee for every notified market area and shall specify its headquarter.

(2) Every Committee established under sub-section (1) shall be a body corporate, having perpetual succession and a common seal, may sue and be sued in its corporate name and subject to the provisions of section 78, be competent to acquire and hold property both movable and immovable and to lease, sell or otherwise transfer

any such property which may have become vested in, or been acquired by it, and to contract and to do all other things necessary for the purposes for which it is established:

Provided that no Committee shall permanently transfer any immovable property except in pursuance of a resolution passed in a meeting specially convened for the purpose by a majority of not less than three-fourth of the members of the Committee and with the prior approval of the Board.

30. (1) A Committee shall consist of sixteen members of whom six shall be *ex-officio* members and ten non-official members.

Constitution
of the
Committee.

(2) *Ex-officio* members:

- (i) Deputy Commissioner . . Vice Chairman;
- (ii) Deputy Director of Agriculture;
- (iii) Deputy Director of Horticulture;
- (iv) Deputy Director of Animal Husbandry;
- (v) Incharge, Krishi Vigyan Kendra; and
- (vi) Secretary of the Committee.

(3) The non-official members shall be appointed by the State Government out of a panel of names given by the Deputy Commissioner concerned equal to twice the number of vacancies to be filled up, in the manner provided here under:—

- (i) nine non-official members from the producers of the notified market area; and
- (ii) one non-official member from the traders registered under section 40, from the notified market area.

31. (1) Subject to the provisions of section 33, every non-official member of the Committee shall hold the office during the pleasure of the State Government.

Term of
office of
the
members of
the
Committee.

(2) The term of an *ex-officio* member of the Committee shall come to an end, as soon as, he ceases to hold the office by virtue of which he was nominated.

32. No person shall be eligible to become a member of the Committee, if he incurs any of the disqualifications specified under section 6 of this Act.

Disqualifica-
tions of
members
of the
Committee.
Removal of
members
of the
Committee.

33. The State Government may, at any time during the period of his office, remove, by notification, any member, if such member has, in its opinion, been guilty of misconduct or neglect of duty or has lost the qualifications on the strength of which he was nominated:

Provided that before the Board notifies the removal of a member under this section, the reasons for his proposed removal shall be communicated to the member concerned and he shall be given an opportunity of tendering an explanation in writing:

Provided further that any vacancy of the non-official member arising as a

result of death, resignation, retirement, transfer or removal shall be filled in as early as practicable.

Meeting of
the
Committee.

34. (1) Committee shall meet for the transaction of its business at least once in three months provided that the committee may in special circumstances meet at any time and at any place in the market area.

(2) The Chairman shall preside over meetings of the Committee and if he is absent, the Vice-Chairman shall preside over the meeting of the Committee and if at any meeting both the Chairman and Vice-Chairman are absent, such one of the members present in the meeting as may be chosen by the members present may act as a Chairman.

(3) Subject to the provisions of this Act, the Committee shall conduct its business as may be prescribed.

Election of
the
Chairman
of the
Committee.

35. Every Committee shall elect from amongst its members a Chairman:

Provided that only producer members of the Committee shall be eligible for election of the Chairman.

Resignation
by the
Chairman
of the
Committee.

36. (1) Chairman or any non-official member of the Committee may resign his office at any time, in writing addressed to the Chairman of the Board and the seat of such Chairman or non-official member shall become vacant on the date of acceptance of his resignation.

(2) During the vacancy caused by death, resignation, removal or otherwise in the office of the Chairman, then notwithstanding anything contained in this Act, such producer member of the Committee as the Chairman of the Board may appoint, shall exercise the powers and perform the functions of the Chairman till the Chairman is duly elected.

No
confidence
motion
against the
Chairman
of the
Committee.

37. (1) A motion of no confidence may be moved against the Chairman at a meeting specially convened for the purpose under sub-section (2) and if the motion is passed by a majority of not less than two third of the members of the Committee, he shall cease to be the Chairman of the Committee.

(2) For the purpose of sub-section (1) a meeting of the Committee shall be held within thirty days of the date of receipt of the notice of motion of no confidence.

(3) The Chairman shall not preside over the meeting, but such meeting shall be presided over by such officer of the State Government as may be authorized by it, however, the Chairman shall have the right to speak and otherwise to take part in the proceedings of the meeting.

(4) If the motion of no confidence is failed or if the meeting could not be held for want of quorum, no notice of any subsequent motion of no confidence against the same Chairman shall be made until the expiry of period of six months from the date of such scheduled meeting.

38. No act of the Committee or of any Sub-Committee thereof or of any person acting as a member, Chairman, Vice Chairman, presiding authority or Secretary of the Committee shall be deemed to be invalid by reason only of some defect in the constitution or appointment of such Committee, Sub-Committee, Members, Chairman, Vice-Chairman, presiding authority or Secretary of the Committee or on the ground that they or any of them were disqualified for such office, or that formal notice of the intention to hold meeting of the Committee or of the Sub-Committee was not given duly or by reason of such act having been done during the period of any vacancy in the office of the Chairman, Vice Chairman, or Secretary of the Committee or member of such Committee or Sub-Committee or for any other infirmity not affecting the merits of the case.

Act of the Committee not to be invalidated.

39. (1) Subject to the provisions of this Act, the Committee may,—

Powers and functions of the Committee.

- (a) enforce the provisions of this Act, the rules and bye-laws made thereunder in the notified market area;
- (b) establish a market in the market area and provide such facilities for persons visiting in connection with the purchase, sale, storage, weighment and processing of agricultural produce concerned as the Board may, from time to time, direct;
- (c) do such other acts as may be required in relation to the superintendence, direction and control of market or for regulating marketing of agricultural produce in any place in the market area, and for the purposes connected with the matters aforesaid, and for that purpose may exercise such powers and discharge such functions as may be provided by or under this Act; and
- (d) do all such other acts which may bring complete transparency in pricing system and transactions taking place in the market area.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Committee may,—

- (i) maintain and manage the market yards and sub-market yards within the market area;
- (ii) provide necessary facilities for the marketing and facilitate the transportation of agricultural produce within the market yards and outside the yards and within the sub-market yards and outside the sub-market yards in the market area;
- (iii) regulate, conduct or supervise the auction of notified agricultural produce in accordance with the provisions and procedure laid down under the rules made under this Act or bye-laws of the Committee;
- (iv) regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales, weighment, delivery, payment and all other matters relating to the market of the notified agricultural produce in the manner prescribed;
- (v) provide for the settlement of all the disputes between the seller and the

buyer arising out of any kind of transaction connected with the marketing of the notified agricultural produce and all matters ancillary thereto;

- (vi) take all possible steps to prevent adulteration of the notified agricultural produce;
- (vii) make registration for weighmen and hammals for weighing and transporting of goods in respect of transactions held in the market yards or sub-yards;
- (viii) set up and promote public – private partnership in the management of the markets;
- (ix) promote public – private partnership for carrying out extension activities in its area viz. collection, maintenance and dissemination of information in respect of production, sale, storage, processing, prices and movement of the notified agricultural produce;
- (x) levy, take, recover and receive rates, charges, fees and other sums of money to which the Committee is entitled;
- (xi) regulate the entry of the persons and the vehicles, traffic into the market yard and sub-market yard visiting the market;
- (xii) compound offences committed under this Act (except section 27) or rules and bye-laws made thereunder;
- (xiii) acquire land and dispose off any movable or immovable property for the purpose of efficiently carrying out its duties;
- (xiv) institute or defend any suit, prosecution, action, proceeding, application or arbitration and compromise in such suit, action, proceeding, application or arbitration;
- (xv) keep a set of standard weights and measures in each principal market yard and submarket yard against which weighment and measurement may be checked;
- (xvi) inspect and verify scales, weights and measures in use in a market area and also the books of accounts and other documents maintained by the market functionaries in such form and in such manner as may be prescribed;
- (xvii) arrange to obtain fitness (health) certificate from a veterinary doctor in respect of the animals, cattle, birds etc. which are bought or sold in the market yard or market area;
- (xviii) carry out publicity about the benefits of regulation, the system of transaction, facilities provided in the market yard etc. through various means such as posters, pamphlets, hoardings, cinema slides, film shows, group meetings, electronic media etc; or through any other means considered more effective or necessary;
- (xix) ensure payment in respect of transactions which take place in the market yard to be made on the same day to the seller, and in default to seize the agricultural produce in question alongwith other property of the person concerned and to arrange for re-sale thereof and in the event of loss, to recover the same from the original buyer together with charges for recovery of the losses, if any, from the original buyer and effect payment of the price of the agricultural produce to the seller;
- (xx) recover the charges in respect of weighmen and hammals and distribute the same to the weighmen and hammals if not paid by the purchaser or seller, as the case may be;

- (xxi) collect and maintain information in respect of production, sale, storage, processing prices and movement of the notified agricultural produce and disseminate such information as directed by the Board;
- (xxii) With a view to maintain stability in the market, take suitable measures to ensure that traders do not buy agricultural produce beyond their capacity and avoid risk to the sellers in disposing off the produce and grant licences only after obtaining necessary security in cash as bank guarantee according to the capacity of the buyers; and
- (xxiii) promote and undertake agricultural processing including activity for value addition in agricultural produce.

(3) With the prior sanction of the Board, the Committee may undertake the following functions:—

- (i) construction of roads, godowns, ropeways and other infrastructure in the market area to facilitate the marketing of agricultural produce and for the purpose give funds to the Board;
- (ii) to provide on rent storage facilities for stocking of agricultural produce to agriculturists;
- (iii) to promote and encourage e-trading, Committee may establish regulatory system, create infrastructure and undertake other activities and steps needed thereto;
- (iv) to maintain and circulate from time to time, the data of arrivals and rates of agricultural produces standard-wise brought into the market area for sale as may be prescribed.

40. (1) Every person who, in respect of notified agricultural produce, desires to operate in the market area as a trader, commission agent, weighman, hammal, surveyor, ware houseman, contract farming sponsor, owner or occupier of the processing factory or any other market functionary, shall apply to the Secretary of the Committee for registration or renewal of registration in such manner and within such period as may be prescribed. The Secretary of the Committee shall be the authority to grant registration certificate with the prior approval of the Committee:

Registration
of Market
functionaries.

Provided that any person may buy agricultural produce in the Market yard/ sub-market yard on day to day basis even without getting registered:

Provided further that any person who desires to trade or transact or deal in any notified agricultural produce in more than one market area, shall get registered, for respective function from the Managing Director of the Board.

(2) No broker, trader, weighman, surveyor, godown keeper or other functionaries shall, unless duly registered, carry on his occupation in a notified market area in respect of the notified agricultural produce under this Act.

(3) Every application for such registration shall be accompanied with such fee as may be prescribed.

(4) The Committee may register or renew the registration or refuse registration or renewal of the registration or cancel the registration on any of the following grounds:—

- (i) if the applicant is a minor; or
- (ii) if the applicant has been declared defaulter; or
- (iii) if the applicant has been found guilty under this Act, the rules and bye-laws made thereunder.

Appointment
of the
Secretary
of the
Committee.

41. (1) Every Committee shall have a Secretary who shall be appointed by the State Government in accordance with the recruitment and promotion rules for the post of Secretary of the Committee.

(2) The Secretary of the committee shall be the *ex-officio* Secretary of the Committee and shall be custodian of all the records and properties of the Committee.

Appointment
of Sub-
Committees
and
delegation
of powers.

42. The Committee may appoint a Sub-Committee for the conduct of any work or to report on any matter and may delegate to such sub-committee such of its powers or duties as it think fit.

Powers and
duties of the
Secretary of
the
Committee.

43. The Secretary of the Committee shall exercise and perform the following powers and duties in addition to such other powers and duties as may be specified in this Act, or the rules or bye-laws made thereunder, namely:—

- (i) to convene the meetings of the Committee and the Sub-Committees, if any, and maintain minutes of the meetings thereof;
- (ii) to attend the meetings of the Committee and Sub-Committees and take part in the discussion;
- (iii) to take steps to give effect to the resolution of the Committee and of the Sub-Committees and report all actions taken in pursuance of such resolution to the Committee in the next meeting;
- (iv) to prepare the budget proposal of the Committee;
- (v) to furnish to the Committee such returns, statements, estimates, statistics and reports as the Committee may from time to time, require including following informations :—
 - (a) the fines and penalties imposed on and any disciplinary action taken against the members or the staff and the market functionaries and others;
 - (b) overtrading by the traders;
 - (c) regarding contraventions of the Act, the rules, the bye-laws or the standing orders, if any, by any person;

- (d) regarding the suspension or cancellation of licence by the Managing Director of the Board;
- (e) regarding the administration of the Committee and the regulation of the marketing;
- (vi) produce before the Committee books, registers and other documents, as may be necessary for the transaction of the business of the Committee or the Sub-Committee, and also whenever called upon by the Committee to do so;
- (vii) exercise supervision and control over the acts of all the officers and the servants of the Committee;
- (viii) collect fees and other money leviable by or due to the Committee;
- (ix) be responsible for all money credited to or received on behalf of the Committee;
- (x) make disbursements of all money lawfully payable by the Committee;
- (xi) operate, maintain and transact the Committee fund;
- (xii) report to the Managing Director of the Board, as soon as possible, in respect of fraud, embezzlement, theft or loss of the Committee fund or property; and
- (xiii) prefer complaints in respect of prosecutions to be launched on behalf of the Committee and conduct proceedings, civil or criminal on behalf of the Committee.

CHAPTER-V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT OF THE BOARD AND THE COMMITTEE

44. Every Committee shall levy charge and collect market fee in the manner as may be prescribed on *ad-valorem* basis at the rate not exceeding two rupees for every one hundred rupees as may be fixed by the State Government,—

- (i) on the sale or purchase of the notified agricultural produce, whether brought from within the State or from outside the State into the market area; and
- (ii) on the notified agricultural produce whether brought from within the State or from outside the State into the market area for processing.

45. (1) Market fee specified in section 44 shall not be levied for the second time in any market area within the State provided that market fee has already been paid on that agricultural produce in any market area of the State and the information in this context has been furnished, by the concerned person that the market fee has already been paid in other market of the State.

Single point levy.

(2) On the agricultural produce brought in the market area for commercial transaction or for processing, the market fee shall be deposited by the buyer or processor, as the case may be, in the office of the Committee, within fourteen days but before sale or resale or processing or export outside the market area, such agricultural produce.

(3) In case any notified agricultural produce is found to have been processed,

sold, or resold or despatched outside the market area without payment of market fee payable on such produce, the market fee shall be levied and recovered on five times the market value of the processed produce or value of the agricultural produce, as the case may be.

Marketing
Development
Fund.

46. (1) All money received by or on behalf of the Board shall be credited into a fund to be called the Marketing Development Fund.

(2) All payments made by the Board shall be defrayed out of the said fund.

(3) The Board may for carrying out the provisions of this Act, borrow money from the State Government or may borrow with the previous approval of the State Government,—

- (i) from any other agency; or
- (ii) issue debentures on the authority of any property vested in it or on the security of a part of its future income accruing to it under this Act, or the rules made thereunder.

(4) The Marketing Development Fund shall be utilized by the Board either its own or through public-private partnership for the discharge of functions entrusted to the Board under this Act. Without prejudice to the generality of this provision, the marketing development fund may be utilized for the following purposes:—

- (i) Payment of administrative expenditure of the Board;
- (ii) travelling and other allowances to the employees of the Board, Chairman and its members;
- (iii) Payment of salary, leave allowance, gratuity, compassionate allowance, compensation for injuries or death resulting from accident while on duty, medical aid, pension or provident fund to the persons employed by the Board and leave and pension contribution to the Government servants on secondment;
- (iv) meeting any legal expenses incurred by the Board;
- (v) giving aid to financially weak Committees in the shape of loans and grants on the terms and conditions as prescribed;
- (vi) propaganda and publicity on matters relating to the marketing of agricultural produce;
- (vii) training of the officers and the staff of the Committees and the Board and also to the agriculturists;
- (viii) meeting expenditure in marketing extension activities and etrading;
- (ix) organizing and arranging workshops, seminars, exhibitions etc. on development of marketing;
- (x) maintenance of the office of the Board and construction and repair of its office buildings, rest houses and the staff quarters;
- (xi) general improvement of the regulation of marketing in the State;
- (xii) loans and advances to the employees;
- (xiii) expenses incurred in auditing the accounts of the Board;

- (xiv) providing technical and administrative assistance to the committees, including execution of works;
- (xv) market survey and research, grading and standardization, quality certification of agricultural produce and other allied subjects;
- (xvi) grading and standardization of agricultural produce;
- (xvii) collection and dissemination of market rates and news;
- (xviii) better marketing of agricultural produce; and
- (xix) with the previous sanction of the State Government, any other purpose which is calculated to promote the general interest of the Board, Committees or, national or public interest.

47. (1) An estimate of the annual income and expenditure of the Board for the ensuing year shall be prepared by the Board and submitted for sanction to the State Government not later than first week of February each year. On the sanction of the budget by the State Government, the Board shall have power to operate upon it.

Annual
Budget of
the Board.

(2) The State Government shall sanction and return the budget within two months from the date of the receipt thereof. If it is not received within two months from the date of its submission, it shall be deemed to have been sanctioned.

48. (1) The Board shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report, giving a true and full account of its activities during the previous year, and shall forward a copy thereof to the State Government.

Accounts,
Audit and
annual
report of
the Board.

(2) The accounts of the Board shall be audited annually by the Examiner of the Local Audit Department or by such other person as the State Government may direct.

(3) As soon as the accounts of the Board are audited, the Board shall send a copy of the audit report to the State Government.

(4) Soon after the submission of the audit report under sub-section (3), and the annual report under sub-section (1), by the Board, the State Government shall cause the said reports to be laid before the State Legislative Assembly:

Provided that when the reports are to be laid in the budget session, these shall be laid on the table of the House on the first sitting of the said session:

Provided further that the period intervening the close of the financial year to which the reports pertain and the laying of reports, shall not exceed nine months.

49. (1) Save as provided in sub-section (2) all money received by a Committee shall be paid into a fund to be called the "committee fund" and all expenditure incurred by the Committee under or for the purposes of this Act shall be defrayed out of the said fund. Any surplus remaining with the Committee after such expenditure has been met, shall be invested in such manner as may be prescribed.

Committee
fund.

(2) Any money received by the Committee by way of arbitration fee or as security for costs in arbitration proceedings relating to disputes or any money received by the Committee by way of security deposit, contribution to provident fund or for payment in respect of any notified agricultural produce, or other charges payable by the Committee or such other money received by the Committee as may be provided in the rules or bye-laws, shall not form part of the Committee Fund, and shall be kept in such manner as may be prescribed.

(3) Every Committee, out of its fund, shall pay to the Board, 25 percent of the total market fee collected under section 44 during the year, to meet the expenses of establishment of the Board and expenses incurred in execution of the functions assigned to the Board under this Act.

(4) All money and receipts specified in this section and forming part of the fund of the Committee shall be deposited in any Nationalized Bank or any other Bank having National Computerized Network or in the Himachal Pradesh State Co-operative Bank.

(5) The Secretary of the Committee shall be the Head of office and shall exercise such financial powers as have been conferred under the Financial Rules of the State Government on the Head of office.

Preparation
and sanction
of budget of
the
Committee.

50. (1) Every Committee shall prepare and pass the budget of its income and expenditure for the ensuing year in such manner and in such form and within such period as may be prescribed and shall submit it to the Managing Director of the Board and the Managing Director shall place the same before the Board for approval. The Board shall approve the budget with or without modification within two months from the date of receipt thereof. If the budget is not returned by the Managing Director within two months, it shall be deemed to have been approved.

(2) A Committee at any time during the year for which any budget has been sanctioned, cause a revised or supplementary budget to be passed and sanction in the same manner as if it were an original budget.

(3) No expenditure shall be incurred by a Committee on any item if there is no provision in the sanctioned budget thereof unless it can be met by re-appropriation from saving under any other head. The sanction for re-appropriation may be obtained from the Board provided that in case of re-appropriation from minor heads under one major head, sanction for re-appropriation shall not be required.

Purpose for
which the
Committee
fund may be
expended.

51. Subject to the provisions of section 49, the Committee in order to discharge functions and duties entrusted to it under this Act, may use the Committee fund. Without prejudice to the generality of this provision, the Committee fund may be used for the following purposes, namely:—

- (i) the acquisition of a site or sites for the market;
- (ii) the establishment, maintenance and improvement of the market yard;
- (iii) the construction and repairs of buildings necessary for the purpose of

- the market yard and for convenience or safety of the persons using the market yard;
- (iv) The maintenance of standard weights and measures;
 - (v) the meeting of establishment charges including payments and contributions towards provident fund, pension and gratuity of the officers and servants etc. of the Committee;
 - (vi) Loans and advances to the employees of the Committee;
 - (vii) the payment of interest on the loans that may be raised for the purpose of the market and provisions of sinking fund in respect of such loans;
 - (viii) the collection and dissemination of information relating to crop statistics and marketing in respect of the agricultural produce;
 - (ix) the expenses incurred in auditing the accounts of the Committee and expenses incurred in the maintenance of the offices;
 - (x) payment of honorarium and travelling allowance to the Chairman and other non-official members of the Committee and employees of the Committee as may be prescribed;
 - (xi) contribution to Marketing Development Fund;
 - (xii) contribution to any scheme for the development of agricultural marketing including transport;
 - (xiii) for providing facilities like grading, standardization, quality certification services and communication to agriculturist in the market area;
 - (xiv) incurring expenses on research and development, extension and training to farmers in marketing of agricultural produce;
 - (xv) prevention, in conjunction with other agencies, state, central and others of distress sale of agricultural produce;
 - (xvi) fostering cooperative marketing and assisting cooperative marketing societies in the procurement and profitable disposal of produce particularly the produce belonging to the small and marginal farmers;
 - (xvii) create and promote on its own or through public-private partnership infrastructure and post harvest handling of agricultural produce, cold storages, pre-cooling facilities, pack houses and all such infrastructure to develop modern market systems;
 - (xviii) meeting any legal expenses incurred by the Committee;
 - (xix) on the training and skill enhancement of staff of the Committee; and
 - (xx) with the previous sanction of the Board, any other purpose which is calculated to promote the general interests of the Committee or the notified market area or any other purpose calculated to promote the national interest.

52. (1) The Committee may, with the previous sanction of the Board, raise the money required for carrying out the purposes for which it is established on the security of any property vested in and belonging to the Committee and of any fees leviable by the Committee under this Act. Power to borrow.

(2) The Committee may, for the purpose of meeting the initial expenditure

on lands, buildings and equipments required for establishing the market, obtain loan from the State Government or the Board or other Committees or financial institutions on such conditions, as may be prescribed.

CHAPTER-VI

CONTROL

Inspection
of Markets
and inquiry
into the
affairs of
the
Committee.

53. (1) The Managing Director of the Board may,—

- (a) inspect or cause to be inspected the accounts and offices of the Committee;
- (b) hold inquiry into the affairs of a Committee;
- (c) call from a Committee's return, statement, accounts or reports which he may think fit to require such Committee to furnish;
- (d) require a Committee to take into consideration—
 - (i) any objection on the ground of illegality, inexpediency or impropriety which appears to him to exist to the doing of anything which is about to be done or is being done by or on behalf of such Committee; or
 - (ii) any information he is able to furnish and which appears to him to necessitate the doing of a certain thing by such Committee.

(2) When the affairs of a market are investigated under this section or the proceedings of any Committee are examined by the Managing Director of the Board under section 55, the Chairman, Vice Chairman, Secretary and all other officers and servants and members of such Committee shall furnish such information in their possession in regard to the affairs or proceedings of the Committee as the Managing Director of the Board or other officer authorized, as the case may be, may require.

(3) An officer investigating the affairs of a Committee under sub-section (1) or the State Government examining the proceedings of any Committee under section 54 shall have the power to summon and enforce the attendance of officers or members of the Committee and to compel them to give evidence and to produce documents by the same means and as far as possible in the same manner as is provided in the case of a civil court by the Code of Civil Procedure, 1908. Where the Managing Director of the Board has reason to believe that the books and records of a Committee are likely to be tampered with or destroyed or the funds or property of a Committee are likely to be misappropriated or misapplied, the Managing Director of the Board may issue orders directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Committee and the officer or officers of the Committee responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.

Power to
call the
proceedings
of the
Committee
or the
Board.

54. (1) The Managing Director of the Board or the State Government, as the case may be, may on its own motion or on an application made to it, call for and examine the proceedings of any Committee or of the Board, as the case may be, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision taken or order passed and as to the regularity of the proceedings of the Committee or the

Board, as the case may be. If in any case, it appears to the Managing Director of the Board or the State Government that any such decision or order or proceedings so called for should be modified, annulled, reversed, or remitted for reconsideration it may pass such order thereon as it may deem fit:

Provided that every application to the Managing Director of the Board or the State Government, as the case may be, shall be preferred within sixty days from the date of such decision or order to the Communication of applicant:

Provided further that no such order shall be passed under sub-section (1) without giving a reasonable opportunity of being heard to the parties affected thereby.

(2) The Managing Director of the Board or the State Government, as the case may be, may suspend the execution of the decision taken or order passed by the Committee or the Board, as the case may be, pending the exercise of its powers under sub-section (1).

55. The Managing Director of the Board may, of its own motion, or on report or complaint received, by order prohibit the execution or further execution of a resolution passed or order made by the Committee or its Chairman or any of its officers or servants, if he is of the opinion that such resolution or order is prejudicial to the public interest, or is likely to affect efficient running of the business in any market area, principal market yards or sub-market yards or is against the provisions of this Act or rules or bye-laws made thereunder.

Power to prohibit execution of further execution or resolution passed or order made by the Committee.

56. (1) If in the course of enquiry or inspection under section 53 or in the course of audit under this Act, it is found that any person who is or was entrusted with the management of the Board or the Committee, as the case may be, or any deceased, past or present Chairman, Vice-Chairman, member or any other officer or employee of the Board or the Committee or an officer of the State Government has made or directed by assenting or concurring or participating in any affirmative vote or proceeding related thereto, any payment or application of any money or other property belonging to or under the control of such Committee, to any purpose contrary to the provisions of this Act, rules or bye-laws made thereunder or has caused any deficiency or loss by gross negligence or misconduct or has misappropriated or fraudulently retained any money or other property belonging to the Board or the Committee, the Managing Director of the Board may, on his own motion or on an application, enquire himself or direct any officer subordinate to him duly authorized by him by an order in writing in this behalf to enquire into the conduct of such person.

Liability of Chairman, Vice-Chairman, members and employees for loss, waste or misappropriation etc.

(2) If, on enquiry made under sub-section (1), the Managing Director of the Board is satisfied that there are good grounds for an order under this sub-section, he may make an order requiring such person, or in the case of a deceased person, his legal representative who inherits his estate, to repay or restore the money or property and

any part thereof, with interest at such rate, or to pay contribution and costs or compensation to such extent as the Managing Director of the Board may consider just and equitable:

Provided that no order under this sub-section shall be made unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter:

Provided further that the liability of a legal representative of the deceased shall be to the extent of the property of the deceased which is inherited by such legal representative.

(3) Any person aggrieved by an order made under sub-section (2) may, within thirty days from the date of communication of the order to him, appeal to the State Government and the order of the State Government shall be final and conclusive:

Provided that in computing the period of limitation the time required for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded.

(4) Any order made under sub-section (2) or sub-section (3) shall, on the application of the Secretary of the Board be enforced by any civil court having local jurisdiction in the same manner as if it were a decree of such court, or any sum directed to be paid by such order may be recovered as arrears of land revenue.

(5) If the Managing Director of the Board is satisfied on affidavit, enquiry or otherwise that any person with intention to delay or obstruct the enforcement of any order that may be passed against him under this section is about to dispose of the whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the State, he may, unless adequate security is furnished, direct, the conditional attachments of the said property or such part thereof as he thinks necessary and such attachment shall have the same effect as if attachment is made by a competent civil court.

Members,
officers and
servants of
the Board
and the
Committees
to be public
servants.

57. All members, officers and servants of the Board and the Committee shall be deemed to be public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Prohibition
of trade
allowance.

58. No trade allowance or deduction, other than prescribed by or under this Act or rules or bye-laws made thereunder, shall be made or received by any person in any market area in any transaction in respect of the notified agricultural produce.

Power to
order
production
of accounts,
entry,
inspection
and seizure.

59. (1) The Secretary of the Committee or any officer of the State Government or the Board, empowered by the State Government in this behalf may, for the purposes of this Act, require any person carrying on business in any kind of notified agricultural produce to produce before him the accounts and other documents and to furnish any information relating to stocks of such agricultural produce or purchase, sale, processing, value addition and delivery of such agricultural produce

by such person and also to furnish any other information relating to payment of market fee by such person.

(2) All accounts and registers maintained by any person in the ordinary course of business of any notified agricultural produce and documents relating to stocks of such agricultural produce or purchase, sale, processing, value addition of such agricultural produce in his possession and offices, establishment, godowns, vessels or vehicles of such persons shall be kept open for inspection at all reasonable time by such officers of the State Government, the Board or the Committee as may be authorized by the State Government in this behalf.

(3) If any such officer has reasons to suspect that any person is attempting to evade the payment of any market fee due from him under this Act or that any person has purchased, sold, processed or value added any notified agricultural produce in contravention of any of the provisions of this Act or the rules or the bye-laws in force in the market areas, he may communicate in writing to such person, seize such accounts, registers and documents of such person, as may be necessary, and shall grant a receipt for the same and shall retain the same only so long as may be necessary for examination thereof or for a prosecution.

(4) For the purposes of sub-section (2) or (3) such officer may enter or search any place of business, warehouse, office, establishment, godown, vessel or vehicle where such officer has reason to believe that such person keeps or for the time being has kept accounts, registers or documents of his business, or stock of the notified agricultural produce relating to this business.

(5) The provisions of section 100 (4) to (8) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to a search under sub-section (4).

(6) Where any books of accounts or other documents are seized from any place and there are such entries therein making reference to quantity, quotations, rates, receipts or payment of money or sale or purchase of goods, such books of accounts or other documents shall be admitted in evidence without witness having to appear to prove the same, and such entries shall be *prima-facie* evidence of matters, transactions and accounts purported to have been recorded therein.

60. (1) Every trader, processor, proprietor of a private yard, proprietor of consumer farmer market or commission agent, carrying on business of the notified agricultural produce shall, before the 30th June, every year submit to the Secretary of the Committee a statement of transaction undertaken by or through him during the previous financial years ending on the 31st March, in such form and in such manner as may be the prescribed.

Submission of annual accounts by licensees and registered functionaries and assessment.

(2) The Secretary of the Committee shall accept or reject the statement submitted to him under sub-section (1) after necessary examination and verification on the basis of information duly available in the Committee and shall assess the balance amount payable by the functionary and levy the assessed amount.

(3) Any person aggrieved by the proceedings of the Secretary of the Committee may, within thirty days from the date of Communication of notice to him, appeal to the Committee.

(4) Any officer authorized by the Board may, on his own motion or on application made to the Board start process of re-verification of the statement verified by the Secretary of the Committee within two years from the date of verification and for this purpose such officer shall exercise the powers under section 59; and the re-verification made by such officer shall be final.

Assessment
of market
fee.

61. If any person required to produce accounts or furnish information under sub-section (1) of section 60, fails to produce such accounts or information or knowingly furnishes incomplete or incorrect accounts or information or has not maintained proper accounts of the business of the notified agricultural produce, the Secretary of the Committee, on his own motion, shall assess such person for fee levied under section 44 on the basis of information available with the committee.

Power to
stop
vehicles and
inspect.

62. (1) At any time when so required, any officer of the Board empowered by the Board or any officer of the Committee empowered by the Committee in this behalf, as the case may be, may direct the driver or any other person in charge of the vehicle, vessel or other conveyance to stop such vessel or other conveyance, as long as may reasonably be necessary, and allow such person to examine the contents in the vehicle, vessel or other conveyance and inspect all records relating to the notified agricultural produce carried, and give his name, address and name and address of the owner of the vehicle, vessel or other conveyance and name and address of the owner of the notified agricultural produce carried in such vehicle, vessel or other conveyance.

(2) Persons empowered under sub-section (1) may seize any notified agricultural produce brought into or taken out or proposed to be taken out of the market area in any vehicle, vessel or other conveyance, if he has reason to believe that any fee or other amount due under this Act or the value payable to the seller in respect of such agricultural produce has not been paid.

(3) If any person empowered under sub-section (1) has reason to suspect that any person is attempting to evade the payment of any market fee due from him under section 44 or that any person has purchased or stored any notified agricultural produce in contravention of any of the provisions of this Act or the rules or the bye-laws made thereunder in the market area, he may enter and search any place of business, warehouse, office, establishment or godown where the person empowered under sub-section (1) has reason to believe that such person keeps or has for the time being kept stock of the notified agricultural produce and may seize the stored agricultural produce and such seized notified agricultural produce may be confiscated in favour of the market committee in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.

(4) The provisions of section 100, 457, 458 and 459 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) shall apply to entry, search and seizure under sub-section (1)(2) and (3) as they apply in relation to the entry, search and seizure of property by the police officer. Such seizure shall forthwith be reported by the person aforesaid to a Magistrate having jurisdiction to try the offence under this Act.

63. (1) Any officer or servant of the Committee or the Board empowered by the State Government, by notification, in this behalf shall have the power to remove any encroachment over the property owned by the Board/ or the Committee including the market yard, and the expenses of such removal shall be paid by the encroacher, if he fails to pay such expenses, the same shall be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

Power to remove encroachments in the market yard.

(2) All the Police Officers shall be bound to assist the officers empowered under sub-section (1), when required, in the performance of their duties under this Act, and for that purpose, shall have the same powers which they have in the discharge of their ordinary police duties.

(3) If any officer or servant of the Board or the Committee empowered under sub-section (1) fails to remove the encroachment within the market yard, he shall be punished with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

64. (1) The State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, exempt in whole or in part any agricultural produce brought for sale or bought or sold in the market area specified in such notification, from the payment of market fee for such period as may be specified therein.

Power to grant exemption from market fees.

(2) Any notification issued under sub-section (1) may be rescinded before the expiry of the period specified therein and on rescission such notification shall cease to be in force.

65. Whenever it is found that any amount is due to the Board or a Committee is irrecoverable or should be remitted, or whenever any loss of the Board's or a Committee's money or stores or other properties occur through fraud or negligence of any person or for any other cause and such property or money is found to be irrecoverable, the facts shall be reported to the Board or the Committee, as the case may be, and the Board, with the approval of the State Government, and the Committee, with the approval of the Board, may order the amount or value of the property to be written off as loss irrecoverable or remitted, as the case may be, provided that in case of a Committee, if in any case the amount due or the value of such property is in excess of five thousand rupees, such order shall not take effect without the approval of the State Government.

Power to write off irrecoverable fees etc.

66. Any sum due to the Board or the Committee from any person on account of any charges, costs, expenses, fees, rent and any other account under the provision of this Act or any rules or bye-laws made thereunder shall be recoverable as arrear of land revenue.

Recovery of sums due to the Board or the Committee.

Redressal of disputes between the private market or consumer market and Committee. 67. Dispute between the private market or consumer market and Committee, shall be referred to the Managing Director of the Board or any other officer authorized by the State Government in this behalf and shall be resolved after giving both the parties a reasonable opportunity of being heard:

Provided that the decision of the authority under this section shall be final.

Appeal. 68. (1) Any person aggrieved by an order passed under sections 25, 26 or 40 may prefer an appeal, in such form and in such manner as may be prescribed, to —

- (a) the Committee, where such order is passed by the Secretary of the Committee with in thirty days from the date of order;
- (b) the Board, where such order is passed by the Committee within thirty days from the date of order; and
- (c) the State Government, where such order is passed by the Managing Director of the Board or by the Board, within thirty days from the date of such order.

(2) The Appellate Authority, if it considers necessary to do so, may grant stay of the order appealed against for such period as it may deem fit.

(3) The order passed by the State Government under this section shall be final.

Bar to civil suit and protection to persons acting in good faith. 69. No suit, prosecution or legal proceedings in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Act or rules or bye-laws made thereunder, shall lie against the officer of the State Government or against the Board or any Committee or against any officer or servant of the Board or any Committee or against any person acting under the directions of such Board, Committee or any officer or servant of the State Government, Board or Committee.

Bar to sue in the absence of notice. 70. Notwithstanding anything contained in this Act, no suit shall be instituted against the Board or any Committee, until the expiration of two months after notice in writing stating the cause of action, name and place of abode of the intending plaintiff and the relief which he claims has been delivered or left at its office. Every such suit shall be dismissed unless it is instituted within six months from the date of accrual of the alleged cause of action.

Power of the State Government to amend the SCHEDULE. 71. (1) The State Government may, subject to previous publication, by notification, add to or delete therefrom any of the agricultural produce specified under column-2 in the SCHEDULE and thereupon the said SCHEDULE shall stand amended accordingly.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be, after it is issued, be laid on the table of the Legislative Assembly.

CHAPTER-VII

OFFENCES AND PENALTIES

72. Any person who contravenes any of the provisions of this Act, or any rule or bye-laws or order issued thereunder or fails to perform the duties assigned under this Act shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both: Penalty for Contravention of Act, Rules and Bye-Laws.

Provided that in the case of a continuing contravention, he shall be liable to be punished with a further fine which may extend to fifty rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.

73. Whenever any person is convicted of any offence punishable under this Act, the Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily and pay over to the Board or the Committee, as the case may be, the amount of fee or any other amount due from him under this Act or rules or bye-laws made thereunder and may, recover and pay over to the Board or Committee, as the case may be, costs of the prosecution. Recovery of market dues.

74. No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall take cognizance of any offence punishable under this Act or rule or bye-laws made thereunder except on a complaint made by the Managing Director of the Board or by the Secretary of the Committee or, by any other person duly authorized by the Board or the Committee in this behalf. Cognizance of offences.

75. (1) The Committee may accept, from any person who has committed or is reasonably suspected of having committed an offence under this Act (other than contravention of section 27 of this Act), or the rules or bye-laws, by compounding of such offence,— Power to compound offences.

- (a) where the offence consists of the failure to pay or the evasion of any fee, or other amount recoverable under this Act or the rules or the bye-laws made thereunder in addition to the fee or other amount so recoverable, a sum of money not less than the amount of the fee or other amount and not more than five times the amount of fee or other amount; and
- (b) in other cases a sum of money not exceeding five thousand rupees.

(2) On the compounding of any offence under sub-section (1), no proceeding shall be taken or continued against the person concerned in respect of such an offence, and if any proceedings in respect of that offence have already been instituted against him in any court, the compounding shall have effect of his acquittal.

CHAPTER-VIII

MISCELLANEOUS

Mode of
making
contract.

76. (1) Subject to the provisions of this Act, no contract or agreement on behalf of the Committee for the purchase, sale, lease, mortgage or other transfer of, or acquisition of interest in immovable property shall be executed except with the previous sanction of the Committee.

(2) Save as provided in sub-section (1)—

- (a) Secretary of the Committee may execute contract or agreement on behalf of the Committee where the amount or value of such contract or agreement does not exceed rupees five thousand regarding matters in respect of which he is generally or specifically authorized to do so by a resolution of the Committee;
- (b) The Chairman and the Secretary of the Committee may jointly execute a contract or an agreement on behalf of the Committee when the amount or value of such contract or agreement does not exceed rupees twenty thousand;
- (c) In any case other than those referred to in clauses (a) and (b), a contract or agreement on behalf of the Committee may be executed by the Chairman, Secretary and two other members of the Committee of whom one shall be *ex-officio* member who have been generally or specially authorized by a resolution of the Committee to do so.
- (3) Every contract entered into by the Committee shall be in writing and shall be signed on behalf of the Committee by the person or persons authorized to do so under sub-section (2).
- (4) No contract other than a contract executed under the provisions of sub-section (1), (2) or (3) shall be binding on the Committee.
- (5) Where a contract or agreement is entered into on behalf of a Committee, the Secretary of the Committee shall report the fact to the Committee in its next meeting held after the date of entering into such contract or agreement.

Octroi not
payable on
certain
agricultural
produce.

77. Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the State Government may, by notification, direct that in respect of such agricultural produce, notified under section 19, brought or received within a notified market area, as may be specified in the notification, no octroi shall be payable by any person to a Municipal Committee or Municipal Corporation, as the case may be, from such date as may be specified therein.

78. (1) When any land is required for the purposes of this Act, the State Government may, on the request of the Board or a Committee, as the case may be, requiring it, proceed to acquire land under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894 and on payment by the Board or Committee, as the case may be, of the compensation awarded under that Act and of all other charges incurred by the State Government on account of the acquisition, the land shall vest in the Board or the Committee, as the case may be.

Acquisition of land for the Board and the Committee.

(2) The Board or a Committee shall be deemed to be a local authority for the purposes of the Land Acquisition Act, 1894.

79. (1) When the State Government is of the opinion that the Board has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, it may, by notification published in the Official Gazette, supersede the Board:

Supersession of the Board and the Committee.

Provided that no order of supersession shall be passed unless the State Government has afforded reasonable opportunity to the Board by submitting a written explanation in respect of the allegations against it.

(2) Where the State Government is of the opinion that a Committee has failed in the performance of its functions or discharge of its duties or has exceeded or abused the powers conferred on it by or under this Act, it may, by notification in the Official Gazette, supersede the Committee:

Provided that no order of supersession shall be passed unless the State Government has afforded reasonable opportunity to the Committee of submitting a written explanation in respect of the allegations against it.

(3) Upon publication of the notification superseding a Committee under sub-section (2), all the members including the Chairman shall, cease to hold the office, and the State Government shall take steps to constitute a new Committee under section 30 and till such time a new Committee is constituted, the Board shall make such arrangements for carrying out the functions of the Committee as it may deem fit for the period not exceeding six months and may, for that purpose, direct that all the functions, powers and duties of the Committee and its Chairman, under this Act, shall be performed, exercised and discharged by such person or authority as the Board may appoint in this behalf and such person or authority shall be deemed to be the Committee or the Chairman, as the case may be.

80. (1) If any dispute arises out of any agreement or contract entered into, under the provisions of this Act, rules or bye-laws made thereunder, between the sponsor and contract farming producer or between the Board and the trader or between the Committee and the trader, the same shall be resolved through conciliation and arbitration.

Reference to Arbitrator in case of dispute.

(2) The Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996) shall apply to the conciliation and arbitration proceedings referred under sub-section (1).

81. (1) On and with effect from the date of establishment of the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board under section 3 of this Act, the Himachal Pradesh Marketing Board established under the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, shall stand abolished.

Abolition of the Himachal Pradesh Marketing Board and transfer of its assets and liabilities.

(2) On and with effect from the date of abolition of the Himachal Pradesh Marketing Board under sub-section (1)—

- (a) the members including the Chairman of the Himachal Pradesh Marketing Board shall cease to hold office;
- (b) all properties, funds and dues which are vested in or realisable by the Himachal Pradesh Marketing Board shall vest in and be realisable by the Board; and
- (c) all liabilities which are enforceable against the Himachal Pradesh Marketing Board shall be enforceable against the Board.

(3) All contracts, agreements, and other instruments entered into immediately before the abolition of the Himachal Pradesh Marketing Board under sub-section (1) and to which the Himachal Pradesh Marketing Board is a party or which are in favour of the Himachal Pradesh Marketing Board shall be deemed to have been entered into by, with or for the Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board.

(4) All suits, appeals or other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Himachal Pradesh Marketing Board, immediately before its abolition under sub-section (1), shall be continued or instituted by or against the Board.

Explanation.— For the purpose of this sub-section, legal proceedings includes any proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894).

(5) All employees of the Himachal Pradesh Marketing Board shall, on and from the date of its abolition under sub-section (1), become employee of the Board, and shall hold office in the Board on the same terms and conditions of service and shall continue as such unless and until their terms and conditions of service are altered by the Board with the previous approval of the State Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where any employee of the Himachal Pradesh Marketing Board, by notice in writing given to the Board at any time before the expiry of three months next following the date of abolition of the Himachal Pradesh Marketing Board under sub-section (1), has intimated his intention of not becoming an employee of the Board, he shall cease to be an employee of the Board and shall be entitled to get such gratuity, provident fund and other retirement benefits as are ordinarily admissible to him under the rules or authorization of the Himachal Pradesh Marketing Board immediately before its abolition.

(7) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Himachal Pradesh Marketing Board transferred to the Board or as to

which of the employees serving under the Himachal Pradesh Marketing Board are to be treated as employees of the Board under this section, such dispute or doubt shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

82. (1) On and with effect from the date of establishment of the Agricultural Produce Market Committees under section 29 of this Act, the Market Committees established under the Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969, shall stand abolished.

Abolition of Market Committees and transfer of their assets and liabilities.

(2) On and with effect from the date of abolition of the Market Committees under sub-section (1).—

- (a) the members including the Chairman of the Market Committees shall cease to hold office;
- (b) all properties, funds and dues which are vested in or realizable by the Market Committees shall vest in and be realizable by Agricultural Produce Market Committees; and
- (c) all liabilities which are enforceable against the Market Committees shall be enforceable against the Agricultural Produce Market Committees.

(3) All contracts, agreements, and other instruments entered into immediately before the abolition of the Market Committees under sub-section (1) and to which such Market Committees are a party or which are in favour of such Market Committees shall be deemed to have been entered into by, with or for the respective Agricultural Produce Market Committees.

(4) All suits, appeals or other legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Market Committees, immediately before their abolition under sub-section (1), shall be continued or instituted by or against the respective Agricultural Produce Market Committees.

Explanation.— For the purpose of this sub-section, legal proceedings includes any proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894).

(5) All employees of the Market Committees shall, on and from the date of their abolition under sub-section (1), become employee of the Agricultural Produce Market Committees, and shall hold office in such Market Committees on the same terms and conditions of service and shall continue as such unless and until their terms and conditions of service are altered by the Board with the previous approval of the State Government.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), where any employee of the Market Committees, by notice in writing given to the Board at any time before the expiry of three months next following the date of abolition of the Market Committees under sub-section (1), has intimated his intention of not becoming an employee of the Agricultural Produce Market Committees, he shall cease to be an employee of Agricultural Produce Market Committees and shall be entitled to get such

gratuity, provident fund and other retirement benefits as are ordinarily admissible to him under the rules of the Himachal Pradesh Marketing Board immediately before its abolition.

(7) If any dispute or doubt arises as to which of the properties, rights or liabilities of the Market Committees transferred to the Agricultural Produce Market Committees as to which of the employees serving under the Market Committees are to be treated as employees of the Agricultural Produce Market Committees under this section, such dispute or doubt shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

Power to
make rules.

83. (1) The State Government may after previous publication, make rules, consistent with this Act, for carrying out all or any of the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,—

- (a) the quantity of agricultural produce for retail sale under section 2 (zl);
- (b) the sitting fee and allowances to be paid from the fund of the Board to the Chairman and non-official members of the Board under section 10;
- (c) the procedure and form for the maintaining the accounts of the Board and audit thereof under sub-section (2) (v) of section 11;
- (d) the duties and functions to be discharged by the Agricultural Produce Marketing Standards Bureau for the promotion of grading, standardization and quality certification of agricultural produce under sub-section (2) (xii) of section 11;
- (e) the procedure to be followed in exercise of supervision and control over officers and staff of the Board by the Secretary in the matter of administration, accounts and records and disposal of all questions relating to the service of the employees;
- (f) the powers and duties to be exercised and discharged by the Secretary of the Board under section 12 (iii);
- (g) the procedure to be followed in maintaining records of the proceedings of the meetings of the Board under section 12 (viii);
- (h) the development of infrastructure to establish consumers or farmers markets and the procedure for the sale of agricultural produce by the producer direct to the consumer in the market area under section 23 (1);
- (i) the form of agreement for contract farming and the manner in which a person shall enter into agreement with contract farming producer under section 24;
- (j) the application for grant and renewal of licence for establishment of private yard, consumer and farmer market, the period for which the licence is to be issued, the form of licence and the conditions and the fee to be charged for grant of such licence under section 25 (1);

- (k) the disqualifications for suspension/ cancellation of licence under section 26 (e);
- (l) the maximum quantity which can be sold by the producer direct to any person for domestic consumption and the maximum quantity of the agricultural produce purchase or sale of which can be under taken by petty trader under sub-section (2) of section 27;
- (m) the transparent system to be followed for settlement of price of the notified agricultural produce for sale into the market yard under sub-section (2) of section 28;
- (n) the manner and procedure to be followed by the Committee for the conduct of its business under sub-section (3) of section 34;
- (o) the procedure to be followed by the Committee to regulate the making, carrying out and enforcement or cancellation of agreements of sales weightment, delivery, payment and other matters relating to the market of notified agricultural produce under clause (iv) of sub-section (2) of section 39;
- (p) the form and the manner and procedure to be followed for the maintaining of books of accounts and other documents by the market functionaries under clause (xvi) of sub-section (2) of section 39;
- (q) the procedure and the manner to be followed for maintaining and circulating the data of arrivals and rates of agricultural produce standard-wise brought into the market area for sale under clause (iv) of sub-section (3) of section 39;
- (r) the form of application for registration or renewal of registration, the form of registration/ certificate or renewal of registration certificate, the period within which application for registration or renewal of registration is to be made and the fee for such registration or renewal of registration under section 40 (1) (3);
- (s) the manner and the procedure to be followed by the Committee for levy and collection of market fee under section 44;
- (t) the terms and conditions subject to which financial weak committees may be aided by granting loans and grants out of the marketing development fund under clause (v) of sub-section (4) of section 46;
- (u) the form, time and procedure to be followed in preparation of annual report by the Board under sub-section (1) of section 48;
- (v) the manner in which the surplus remaining with the Committee shall be invested under sub-section (1) of section 49;
- (w) the manner in which any money received by the Committee by way of arbitration fee, security for cost in arbitration proceeding, security deposit, contribution to provident fund, payment in respect of any notified agricultural produce, other charges payable by the Committee or such other money received by the Committee under the rules or bye-laws, shall be kept under sub-section (2) of section 49;
- (x) the form, procedure and manner and the period within which the

Committee shall prepare and pass the budget and its income and expenditure for the ensuing year under sub-section (1) of section 50;

- (y) the manner and procedure for payment of honorarium and travelling allowance to the Chairman and other non-official members of the Committee and to the employees of the Committee under clause (x) of section 51;
- (z) the conditions subject to which the Committee for the purpose of meeting the initial expenditure on lands, buildings and equipments required for the establishment of market, may obtain loan from the State Government or the Board or other Committees or financial institutions under sub-section (2) of section 52;
- (za) the form and the manner in which a statement of transaction shall be submitted to the Secretary of the Committee for the previous financial year ending on 31st March under sub-section (1) of section 60;
- (zb) the form and the manner in which an appeal may be filed under sub-section (1) of section 68; and
- (zc) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of fifteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, Assembly agrees in making any modifications in the rules or Assembly decides that the rule should not be made, such rules shall have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be. However, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything done earlier under that rule.

(4) Every rule made under this shall, as soon as may be after they are made be laid before the Legislative Assembly.

Power to
make Bye-
Laws.

84. (1) Subject to any rules made by the State Government under section 83, the Board may, in respect of the notified market area, make bye-laws for,—

- (i) the regulation of business of the Market Committee;
- (ii) the conditions of trading in a market;
- (iii) the delegation of powers, duties and functions to a sub-committee, if any;
- (iv) enabling and regulating e-trading;
- (v) any other matters for which bye-laws are to be made under this Act or it may be necessary to frame bye-laws for effectively implementing the provisions of this Act and the rules made thereunder in the market area;

(2) No bye-law shall take effect until it has been published for information and notified in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

85. Subject to the rules made under this Act, the Board may with the previous approval of the State Government frame regulations for.— Power to make Regulations.

- (a) summoning and holding of meetings of the Board, the time and date when such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings;
- (b) powers and duties of the officers and other employees of the Board;
- (c) salaries and allowances and other conditions of service of officers and other employees of the Board and the Market Committees;
- (d) Management of the property of the Board;
- (e) Execution of contracts on behalf of the Board;
- (f) Maintenance of accounts and the preparation of balance sheet by the Board;
- (g) Procedure for carrying out the functions of the Board under this Act;
- (h) Other matter for which provision is to be or may be made in regulation.

86. The Himachal Pradesh Agricultural Produce Markets Act, 1969 (Act No. 9 of 1970), is hereby repealed: Repeal and savings.

Provided that such repeal shall not affect,—

- (a) the previous operation of the Act so repealed or anything duly done or suffered thereunder, or
- (b) the right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Act, or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed Act, or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid; and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act has not been enforced:

Provided further that subject to the preceding proviso anything done or any action taken (including any appointment, or delegation made, notification, notice, order, instruction or direction issued, rules, regulation, bye-laws, form, scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted, registration affected, fee levied), under the repealed Act shall, in so far as it is in force immediately before the coming into force of this Act and is not inconsistent with the provisions of this Act be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

THE SCHEDULE**[See section 2 (a) and section 71]**

Item	English Name	Hindi Name
1	2	3
1. Cereals	1. Paddy	Dhan
	2. Rice	Chawal
	3. Wheat	Kanak
	4. Maize	Makki
	5. Barley	Jau
	6. Buck Wheat	Kutu
2. Pulses	1. Pigeon pea	Arhar
	2. Lentil	Massur
	3. Black gram	Urd
	4. Green gram	Moong
	5. Peas dry	Matar khushk
	6. Cow peas	Lobhia
	7. Pulses split	Dal Dali
	8. Gram	Chana
	9. French bean/ Soyabean.	Rajmash/Bhararh.
3. Oilseeds	1. Mustard	Sarson
	2. Indian rape	Toria
	3. Linseed	Alsi
	4. Groundnut shelled and unshelled.	Mungphali
	5. Sesamum	Til
4. Fruits	1. Mango	Am
	2. Banana	Kela
	3. Lichies	Lichies
	4. Sweet orange	Malta
	5. Lemon	Neemboo
	6. Grapes	Angoor
	7. Pomegranate-seed.	Anardana
	8. Apple	Saib
	9. Orange	Sangtra
	10. Peach	Aru
	11. Plum	Alucha
	12. Pears	Naspati
	13. Guava	Amrud

1	2	3
	14. Chilgoza	Niyoz
	15. Apricot	Khurmani
	16. Persimon	Japani Phal
	17. Watermelon	Tarbuz
	18. Walnut	Akhrot
	19. Almond	Badam
	20. Musk-Melon	Kharbooza
	21. Papaya	Papita
5. Vegetables	1. Potatoes	Alu
	2. Onion dry	Piaz Khushk
	3. Brinjal	Baingan
	4. Bottle gourd	Ghia
	5. Lady's finger	Bhindi
	6. Red gourd	Halwa Kadu
	7. Tomato	Tamator
	8. Cauliflower	Phulgobhi
	9. Cabbage	Bandhgobhi
	10. Sponge gourd	Ghia-tori
	11. Green peas	Matar hari
	12. French bean	Pharas bean
	13. Leaves of Indian colza mustard and spanich etc.	Sag
	14. Carrot	Gajar
	15. Raddish	Muli
	16. Turnip	Salgam
	17. Tinda gourd	Tinda
	18. —	Kathal
	19. —	Zami Kand
	20. Arum	Arbi
	21. —	Kachalu
	22. Fenu greek	Methi hari
	23. Hill capsicum	Mirch badi
	24. Bitter gourd	Karela
	25. Ash gourd	Petha
	26. Cucumber	Khira
6. Fibres	1. Cotton ginned and unginned.	Kapas aur Rui
7. Animal Husbandry Products.	1. Poultry	—
	2. Eggs	Anda
	3. Cattle	—
	4. Sheep	Bhed
	5. Goat	Bakri
	6. Wool	Oon

1	2	3
	7. Butter	Makhan
	8. Ghee	Ghee
	9. Milk	Dudh
	10. Goat meat and Mutton.	Bakri-aur Bhed-ka-gosht.
	11. Fish	Machhali.
8. Condiments, spices and other.	1. Ginger	Adarak
	2. Garlic dry	Lahasn khushk
	3. Chillies dry and green.	Mirch
	4. Turmeric	Hali
	5. Coriander	Dhaniya khushk and hara.
9. Narcotics	1. Tobacco	Tambaku
10. Miscellaneous	1. Sugarcane	Ganna
	2. Gur and Shakkar	Gur aur Shakkar
	3. —	Khandsari
	4. Bark of walnut	Dandassa
	5. —	Dhoop
	6. Edible mushroom	Guchi
	7. —	Banakhsha
	8. Bhabar grass	Bhabar ghas
	9. Discoria	Singli-Mingli
	10. Kmrui Patti/Pathis.	Pattis
	11. Catechu	Katha
	12. Viola	Ambla
	13. Sausarealappa	Kuth
	14. Timber	Imarti Lakri.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Agricultural Marketing is witnessing major changes world over, owing to the liberalization of agricultural commodities. To enable the farming community to derive maximum value from the new market access opportunities both at home and globally, the internal marketing system in the country needs to be modernized, integrated and strengthened. In this context, the Government of India, Ministry of Agriculture appointed an Expert committee which suggested various reforms relating to agricultural marketing system as well in policies and programmes for development and strengthening of agricultural marketing in the country. The reports have noted that the control over agricultural markets by the State has to be eased to facilitate greater participation of the private sector, particularly to engender massive investments required for the development of marketing infrastructure and supporting services. The recommendations contained in these reports have been discussed with the State Agriculture Ministers in various conferences organized by the Ministry of Agriculture, Government of India. In these conferences, the State Government has expressed the view that reforms in the agricultural marketing sector are necessary to move away from a regime of controls to one of regulation and competition. While promoting the alternative marketing structure, the State Government also needs to put in place adequate safe-guards to avoid any exploitation of farmers/producers by the private traders and industries. For this, there was a need to formulate fresh legislation on agricultural marketing. The Ministry of Agriculture, Government of India has sent a draft model legislation to the State Governments for making their State Acts on the subject in conformity with the Model legislation.

The provisions of the existing Himachal Pradesh Agricultural Produce Market Act, 1969 are not sufficient in addressing these issues. Therefore, it is considered necessary to establish new institutions under an appropriate legislation. Hence, it has been decided to re-enact a law to establish Himachal Pradesh State Agricultural Marketing Board and Agricultural Produce Market Committees.

The proposed legislation provides for establishment of private markets and yards, consumer/farmers markets for direct sale and promotion of public-private partnership in the management and development of agricultural markets in the State. It also provides for regulation and promotion of contract-farming in the State, prohibit commission agency in any transaction of agricultural produce with the producers, and creation of post harvest management facilities at the farm level by the farmers and agriculturists for their bonafide use for which Central/State Government may provide different schemes.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

Dated..... 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of this Bill, after being enacting, are to be enforced through the existing Government machinery, therefore, there shall be no additional expenditure out of the State ex-chequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 83 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules and clauses 84 and 85 seek to empower the Board to make bye-laws and regulations respectively for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

**THE HIMACHAL PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND
REGULATION) BILL, 2005**

A

BILL

to re-enact the law to provide for improved regulation in marketing of agricultural produce, development of efficient marketing system, promotion of agriprocessing and agricultural exports establishment and proper administration of markets for agricultural produce in the State of Himachal Pradesh and to ensure level playing field for competitive markets to operate through setting of minimum standards for facilities, procedures and systems, thereby promoting the establishment of well administered and efficient infrastructure for marketing of agricultural produce in and from the State of Himachal Pradesh.

RAJ KRISHAN GAUR,
Minister-In-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR
Secretary (Law).

SHIMLA :

The 2005.

